

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» त्या थैरेपिस्ट बन संवारे कैरियर...



लालटेन का तेल खत्म: राजनाथ

डायनासोर की तरह कांग्रेस भी हो जाएगी खत्म



काराकाट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दावा किया कि मुफ्त राशन योजना के तहत, लोगों को उनकी खपत से अधिक खाद्यान्न मिल रहा था। पूर्व भाजपा अध्यक्ष, जो बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में खाद्य मुद्रास्फीति दर दुनिया में सबसे कम थी और मूल्य वृद्धि के आरोपों पर निराशा व्यक्त की। यह दावा करते हुए कि केंद्र सरकार ने लोगों को शौचालय और पक्के मकान जैसे कल्याणकारी उपाय प्रदान करके कोई उपकार नहीं किया है, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सेवा की भावना के साथ राजनीति में हैं।

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और उसके बिहार सहयोगी राजद को इन तथ्यों पर उनका मुकाबला करने की चुनौती दी। सिंह ने कहा,

अगर कोई गलती है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं की। अपने लगभग 30 मिनट लंबे भाषण में, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया और दावा किया कि यह जल्द ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी, और उन्होंने राजद की तुलना पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन से की, जिसकी लौ तेल सूखने के बाद से अस्थिर हो गई थी। सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की और दावा किया कि उनके शासन में भारत को अब कमजोर देश के रूप में नहीं देखा जाता।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान अब आतंकवादियों को भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता...रूस और यूक्रेन वहां फंसे हमारे छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए युद्ध रोकने पर सहमत हुए। उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने और तीन तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए भी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, हम ऐसी किसी भी प्रथा को स्वीकार नहीं करते हैं जो हमारी बहनों और बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। हम वोटों की प्रवाह किए बिना काम करते हैं।

मोदी के मौन व्रत से कांग्रेस को ऐतराज

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित मौन व्रत में हस्तक्षेप करने की अपील के साथ भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क किया है। मोदी ने पहले कहा था कि 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के बाद वह कन्याकुमारी जाएंगे और ध्यान करेंगे। प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने महत्वपूर्ण चुनावी घटनाओं की पूर्व संख्या पर पीएम मोदी के मौन व्रत के संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। चुनाव आयोग के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद सिंघवी ने एएनआई को दिए एक बयान में प्रतिनिधिमंडल के विवाद के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग से कहा कि 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।



दिल्ली में रिकॉर्ड 52.3 डिग्री तापमान

बारिश के बाद राहत मिली

नई दिल्ली। राजधानी में रिकॉर्ड 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, लेकिन दिल्लीवालों को बारिश के बाद राहत मिली।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद राहत मिली, राजधानी में रिकॉर्ड 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत मिली, क्योंकि बारिश की बौछारों ने क्षेत्र को राहत पहुंचाई, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुंगेशपुर में अभूतपूर्व अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राजधानी में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यह भीषण गर्मी मंगलवार के अत्यधिक तापमान के बाद आई है, जहां मुंगेशपुर में इसी मौसम केंद्र ने 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था।



इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है, जिसके अनुसार अगले 24 घंटों के भीतर केरल में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियाँ अत्यधिक अनुकूल हैं। इस विकास से दक्षिण अरब सागर के अतिरिक्त भागों, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के शेष भागों, साथ ही

दक्षिण-पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में और अधिक प्रगति होने की उम्मीद है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 मई से 2 जून तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तथा 29 से 31 मई तक जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में गरज और बिजली के साथ छिटपुट से

लेकर छिटपुट हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 30 मई से 2 जून तक छिटपुट हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि 31 मई से 2 जून तक राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वर्तमान में पूर्वोत्तर असम और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले सात दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ व्यापक रूप से व्यापक से लेकर व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले पांच दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

अंतिम चरण की 13 सीटों के लिए आज से थम जाएगा चुनाव प्रचार

लखनऊ। लोकसभा चुनावों के सातवें और अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान एक जून को होगा। इसी के साथ दुद्धी (अजजा) विधानसभा उप चुनाव के लिए भी वोट पड़ेंगे। इन सीटों के लिए प्रचार अभियान बृहस्पतिवार से थम जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी।

उन्होंने बताया कि सातवें चरण की इन सभी लोकसभा सीटों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं, सोनभद्र के दुद्धी

(अजजा) विधानसभा उप चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान समाप्त होने से



पहले के 48 घंटे यानी बृहस्पतिवार शाम छह बजे से चुनाव प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लग जाएगा। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त

होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सातवें चरण का चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित न रहें।

मतदान के दिन मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक है।

इन 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग

13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 2 आरक्षित हैं। इस चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में महाराजगंज, गोरखपुर, गुशीनगर, देवरिया, बांशगांव (अजा), घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्टसगंज (अजा) हैं।

वोटों को गर्मी से बचाने के निर्देश दिए गए हैं

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए मतदेय स्थलों में आवश्यक प्रबंध किये गये हैं। मतदान केन्द्रों में ठंडा पानी, शौचालय और दिव्यांग व वृद्धों के लिए व्हील चेयर व कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। पोलिंग स्टेशन परिसर में मतदाताओं की कतार तक छाया के इंतजाम किये गये हैं। लू से बचाव के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर पैरामेडिक्स व आशा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में ओआरएस एवं मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पैरामेडिक कर्मी भी तैनात किए गए हैं। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को अलग-अलग नों पर रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से मतदान केन्द्रों व मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर भेजा जा सके।

बंगाल को धन मुहैया कराने को लेकर प्रधानमंत्री फैला रहे हैं झूठ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर राज्य को धन उपलब्ध कराने के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र के मेटियाबुरुज में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं लेकिन राज्य में सीए (नागरिकता संशोधन कानून), एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसी

विभाजनकारी राजनीति की अनुमति नहीं देंगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बंगाल में रैलियों को किया है। यह सरासर झूठ है। बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समिक भास्कराचार्य ने कहा, प्रधानमंत्री ने तुणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि तुणमूल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी से प्रतिबिंबित होता है कि वह बेनकाब होने के बाद घबरा गई हैं।

संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि केंद्र ने राज्य के लिए धन भेजा जिसे तुणमूल कांग्रेस ने हड़प लिया। वह कह रहे हैं कि केंद्र ने धन भेजा था लेकिन वह हमने लूट लिया। प्रधानमंत्री झूठ बोल

महात्मा गांधी को लेकर मोदी के बयान पर मचा सियासी घमासान

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया कि दुनिया को रिचर्ड एटनबरो की 1982 की जीवनी पर आधारित फिल्म गांधी की रिलीज तक महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता था। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि सिर्फ 'एंटार्प्राइज पॉलिटेकनल साइंस' के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिये फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बुधवार को अपने इस दावे पर कांग्रेस की आलोचना की कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने से पहले तक दुनिया महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानती थी। समाचार चैनल एबीपी को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने दावा किया कि महात्मा गांधी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे लेकिन दुनिया उनके बारे में नहीं जानती थी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या पिछले 75 वर्षों में गांधी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना देश की जिम्मेदारी नहीं थी। महात्मा गांधी दुनिया की एक महान आत्मा थे।

बेमेतरा फैक्ट्री हादसा: मृतक और लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधन देगी सहायता राशि

रायपुर. बेमेतरा जिले के बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में 1 मजदूर की मौत हुई है। वहीं 8 मजदूर लापता हैं। इस मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि घटना में 1 मृतक एवं 8 लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधन की ओर से 30-30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बता दें कि बेमेतरा स्थित बारूद फैक्ट्री हादसे की मजदूरों को मृतक राशि दी गई है। बेरला SDM पिंकी मनहर के नेतृत्व में फैक्ट्री में ब्लास्ट की न्यायिक जांच 4 बिंदुओं पर की जाएगी। वहीं इस मामले में अब तक प्रशासन की तरफ से स्पेशल ब्लास्ट कंपनी प्रबंधन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

प्रमुख समाचार

सारी ज़िंदगी भी मुझे जेल में रखें, तो भी...केजरीवाल



नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है कि कथित शराब नीति घोटाला में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जालंधर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएम कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? केजरीवाल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हालिया साक्षात्कार में पीएम मोदी की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामला निराधार था, क्योंकि इसमें शामिल कथित धन की कोई वसूली नहीं की गई थी। एक इंटरव्यू में पीएम से पूछा गया कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मामले में कोई सबूत नहीं मिला है। पीएम ने कहा कि कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कोई वसूली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसे छिपाने के लिए उन्होंने कहा कि केजरीवाल अनुभवी चोर हैं। यह गलत गिरफ्तारियों को सही साबित करने का एक बहाना है। जब आपने स्वीकार कर लिया है कि उत्पाद शुल्क घोटाला गलत है।

अफवाहें फैला रहे हैं भाजपा के लोग: नवीन पटनायक



नई दिल्ली। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बिगड़ती सेहत की जांच के लिए विशेष समिति बनाने के पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर बीजद प्रमुख ने पलटवार किया है। नवीन पटनायक ने कहा कि मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक बैठक में कहा है कि मेरी तबीयत खराब है और वह इस मामले की जांच कराना चाहते हैं। यदि वह मेरे स्वास्थ्य के बारे में इतना चिंतित थे तो उसे बस एक टेलीफोन उठाना था और मुझे फोन करना था और मुझे मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछना था। पटनायक ने कहा कि भाजपा में ऐसे कई लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों से मेरे स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को आश्चर्य करता हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पिछले एक महीने से हमारे राज्य में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। एक रैली को संबोधित करते समय हाथ कांपने का वीडियो वायरल होने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कहा है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्ता में आती है तो वे पटनायक के बिगड़ते स्वास्थ्य की जांच कराएंगे।

एलजी ने स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज के ओएसडी निलंबित



नई दिल्ली। एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) डॉ. आरएन दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वीके सक्सेना ने निजी नर्सिंग होम के अनियमित और अवैध पंजीकरण में कथित संलिप्तता के लिए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी डॉ. आरएन दास को निलंबित करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने से छह नवजात शिशुओं की मौत के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। दास को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, दस्ताने, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) किट जैसी लगभग 60 रुपये की विभिन्न वस्तुओं की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में अप्रैल में सतर्कता निदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों बुधवार को जारी आदेश में, निदेशालय ने कहा, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम -10 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य), जीएनसीटीडी के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) डॉ. आरएन दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

महात्मा गांधी को लेकर मोदी के बयान पर मचा सियासी घमासान



नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया कि दुनिया को रिचर्ड एटनबरो की 1982 की जीवनी पर आधारित फिल्म गांधी की रिलीज तक महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता था। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि सिर्फ 'एंटार्प्राइज पॉलिटेकनल साइंस' के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिये फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बुधवार को अपने इस दावे पर कांग्रेस की आलोचना की कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने से पहले तक दुनिया महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानती थी। समाचार चैनल एबीपी को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने दावा किया कि महात्मा गांधी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे लेकिन दुनिया उनके बारे में नहीं जानती थी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या पिछले 75 वर्षों में गांधी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना देश की जिम्मेदारी नहीं थी। महात्मा गांधी दुनिया की एक महान आत्मा थे।

बेमेतरा फैक्ट्री हादसा: मृतक और लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधन देगी सहायता राशि



रायपुर. बेमेतरा जिले के बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में 1 मजदूर की मौत हुई है। वहीं 8 मजदूर लापता हैं। इस मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि घटना में 1 मृतक एवं 8 लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधन की ओर से 30-30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बता दें कि बेमेतरा स्थित बारूद फैक्ट्री हादसे की मजदूरों को मृतक राशि दी गई है। बेरला SDM पिंकी मनहर के नेतृत्व में फैक्ट्री में ब्लास्ट की न्यायिक जांच 4 बिंदुओं पर की जाएगी। वहीं इस मामले में अब तक प्रशासन की तरफ से स्पेशल ब्लास्ट कंपनी प्रबंधन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

जालंधर लोकसभा सीट पर दल-बदलुओं का मेला

जालंधर लोकसभा सीट ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। पार्टी ने 1952 के बाद से तीन उपचुनावों सहित 20 चुनावों में 15 बार सीट जीती है। हालांकि, 2023 के उपचुनावों में परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया, जब कांग्रेस के करमजीत कौर को कांग्रेस विधायक से आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार बने सुशील रिंकू ने हराया था। कौर भी अब भाजपा में हैं और कांग्रेस द्वारा उन्हें जालंधर से टिकट नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया है। कौर को 2023 के उपचुनाव में मैदान में उतारा गया था क्योंकि उनके पति चौधरी संतोख सिंह, जालंधर से मौजूदा कांग्रेस सांसद, की राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई थी।

कांग्रेस का अभेद किला

कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली जालंधर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किसी जमाने में देश के 12वें प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने किया था। कांग्रेस ने अपने अभेद किले को बचाने के लिए दलित नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में

उतारा है। चन्नी रूपनगर जिले की चमकौर साहिब सीट से विधायक थे। आम आदमी पार्टी (आप) ने दो बार के विधायक और अकाली दल के पूर्व नेता पवन कुमार टिन्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। टिन्नी अप्रैल में ही सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मौजूदा सांसद सुशील रिंकू पर दांव लगाया है। रिंकू को आप ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया था लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन लिया और जालंधर सीट से नामांकन दाखिल किया। रिंकू पिछले वर्ष कांग्रेस को छोड़कर आप में शामिल हुए थे। सुखबीर सिंह बादल नीत शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख व पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह कायपी को चुनाव मैदान में उतारा है।

16.54 लाख वोटर्स करंगे फैसला

जालंधर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16.54 लाख मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 37 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है। इस लोकसभा सीट में नौ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें फ़िलौर (अजा), नकोदर, शाहकोट,



कस्तारपुर (अजा), जालंधर वेस्ट (अजा), जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ, जालंधर कैंट और आदमपुर (अजा) शामिल हैं। प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार चन्नी क्षेत्र के मतदाताओं को अपने विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब में किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। चन्नी कहते हैं, मैं यहां रहने आया हूँ। मेरे पूर्वज यहीं के हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। वहीं भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुशील रिंकू को

केंद्र की मोदी सरकार के 10 वर्षों के प्रदर्शन पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव 2019 में जालंधर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार संतोख चौधरी ने जीत हासिल की थी। हालांकि, जनवरी 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में रिंकू ने जीत हासिल की थी। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीट के लिए मतदान एक जून को होगा।

उमरा ऑपरेशन ब्लू स्टार का भूत

इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा आयोजित रैलियों में एक प्रमुख पोस्टर सर्वव्यापी है। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर में क्षतिग्रस्त अकाल तख्त की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें बादल ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 1 जून को मतदान करते समय यह याद रखें कि कांग्रेस ने 1984 में क्या किया था। राज्य भर में इसी तरह के बड़े आकार के पोस्टर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा लगाए गए हैं, जो सिखाओं की सर्वोच्च निर्वाचित संस्था है, जो

एसएडी द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि पार्टी इसका फायदा उठाकर अपनी पंथिक राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तथ्य यह है कि 1 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है - आतंकवादियों से सिखाओं के पवित्र मंदिर को खाली कराने के लिए सेना की विवादास्पद कार्रवाई।

जबकि कांग्रेस पोस्टरों का मुख्य लक्ष्य है क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इंदिरा गांधी ने केंद्र में सरकार का नेतृत्व किया था - जो 1 जून से 6 जून 1984 तक चला - आम आदमी पार्टी (आप) और शिअद को भी कुछ वोटों का नुकसान हो सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों में नतीजे प्रभावित हो सकते हैं वे हैं फरीदकोट, संगरूर और खडूर साहिब और कुछ हद तक बठिंडा। जबकि स्वर्ण मंदिर अभियान को लेकर इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक बेअंत सिंह का बेटा फरीदकोट में उम्मीदवार है। संगरूर में, कट्टरपंथी शिअद (ए) नेता सिमरनजीत सिंह मान मौजूदा सांसद हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं। विवादास्पद उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से उम्मीदवारों में से एक हैं।

इंद्रावती एरिया कमेंटी में सक्रिय 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दत्तेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वरार्द के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार संपर्क एवं संवाद कर शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, वहीं लगातार हो रहे मुठभेड़ों में मारे जा रहे नक्सलियों के परिणाम स्वरूप इंद्रावती एरिया कमेंटी में सक्रिय 10 नक्सलियों ने बुधवार को दत्तेवाड़ा एसपी गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित सभी नक्सली बंद के दौरान रोड़ खोदना, पेड़ काटना और बैनर पोस्टर लगाने की वारदातों में शामिल रहे हैं।



दत्तेवाड़ा एसपी गौरव राय ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि तात्कालिक रूप से प्रदान की गई। साथ ही पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ दिए जायेंगे। विदित हो कि लोन वरार्द अभियान के तहत अब तक 180 इनामी नक्सलियों सहित 815 नक्सली आत्मसमर्पण का चुके हैं।

पण्डरू पोडियाम (रेखावाया आरपीसी/जनताना सरकार दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ सदस्य), कुमारी रामवती जुर्दा पिता मुरा जुर्दा (रेखावाया आरपीसी/जनताना सरकार मिलिशिया सदस्य), सुशील पोडियाम पिता सुकू पोडियाम (रेखावाया आरपीसी/जनताना सरकार मिलिशिया सदस्य), बामन मड़काम पिता स्व. भीमा मड़काम (रेखावाया आरपीसी/जनताना सरकार मिलिशिया सदस्य), रानू कोवासी पिता स्व. संतु कोवासी (रेखावाया आरपीसी/जनताना सरकार मिलिशिया सदस्य), जोगा माडुवी पिता स्व. मुंगडू माडुवी (रेखावाया आरपीसी/जनताना सरकार मिलिशिया सदस्य), बामन माडुवी पिता स्व. मासा माडुवी

के पास से विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है।

जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि केरलापाल, मलगेर एरिया कमेंटी के नक्सलियों की एक मीटिंग की सूचना पर 27 मई को थाना केरलापाल से जिला बल, डीआरजी सुकमा, डीआरजी बस्तर का बल 206 वाहिनी कोबरा का बल संयुक्त पार्टी ग्राम सिमेल, गोगुण्डा, गडगुड़ खुंडुशपारा व आस-पास क्षेत्र की ओर भेजा गया।

28 मई को सिमेल के जंगल-पहाड़ी से एक हार्डकोर महिला नक्सली बारसे मुये पिता बारसे देवा (दरभा डिवीजन मेडिकल टीम प्रभारी एवं मलगेर एरिया कमेंटी सदस्य) जिस पर पांच लाख का इनाम था को गिरफ्तार किया गया है।

महिला ग्राम पोटाली, उरलपारा थाना अरनपुर जिला दत्तेवाड़ा की निवासी थी, महिला नक्सली के पास से 1 नग टिफिन बम, 5 नग डेटोनेटर, 5 नग बैटरी, 9 नग नक्सल साहित्य, मेडिकल किट व अन्य नक्सली सामग्री बरामद किया गया।



बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सली डेर

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जिसमें पुलिस ने दो नक्सलियों को डेर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महेड़ पीएस सीमा के अंतर्गत वन क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। एसपी बीजापुर जितेंद्र यादव का कहना है कि महेड़ पीएस सीमा के अंतर्गत वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मारे गए दोनों नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली कि थाना महेड़ के तहत कोरंजेड़-बन्देपारा के जंगलों में महेड़ एरिया कमेंटी एसीएम बुचना, विश्वनाथ, बामन एवं अन्य 15-20 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति है। जानकारी मिलने के बाद डीआरजी बीजापुर की टीम को 27 मई को रवाना किया गया था। इस बीच आज बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई।



पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष नक्सली को मार गिराया। साथ ही मौके से हथियार, वायरलेस सेट, विस्फोटक व नक्सली सामग्री तथा रोजमर्रा के सामान बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है मुठभेड़ में एक टॉप लीडर महिला नक्सली भी मारी गई है जिस पर पर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित है। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस की तरफ से अब तक नहीं की गई है।

पालिका अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, पार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

खैरागढ़। डोंगरगढ़ शहर की राजनीति में लगातार सियासी उठापटक चल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम के खिलाफ भाजपा के 14 पार्षदों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद से ही कांग्रेस की डोंगरगढ़ शहर सरकार गिरती नजर आ रही है। भाजपा पार्षद दल की कार्यवाही से बौखलाई कांग्रेस ने आनन फानन में नगर पालिका उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा के खिलाफ भी अपने 7 पार्षदों के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ज्ञापन सौंपा है।



पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम की माने तो नगर पालिका उपाध्यक्ष उमामहेश वर्मा के पार्टी बदलने के बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्षदों में आक्रोश है। पीआईसी का काम भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। पूरे मामले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजयराज सिंह ने कहा, राजनैतिक स्वार्थ के लिए अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर उपाध्यक्ष उमामहेश वर्मा ने बताया कि वे दो बार निर्दलीय पार्षद के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने कभी कांग्रेस प्रवेश नहीं किया। अध्यक्ष सुदेश मेश्राम से शहर के विकास को लेकर काफी उम्मीद थी, परंतु उन्होंने चार साल केवल भ्रष्टाचार ही किया है, इसी के चलते वे भाजपा में गए हैं।

फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव को महज कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ ही अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी खुलकर देखने को मिल सकती है, जिससे कि अपनी अपनी पार्टी के कुनबे को बढ़ाया जा सके।

नीनु इटियेरा ने रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया

बिलासपुर/रायपुर। सुश्री नीनु इटियेरा ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 1988 बैच की भारतीय रेल परिचालन सेवा की अधिकारी सुश्री इटियेरा इससे पूर्व में दक्षिण रेलवे, चन्नई में प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने दक्षिण रेलवे में प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के पद भी कार्य किया है। सुश्री नीनु इटियेरा ने दक्षिण रेलवे के मद्रुरै मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के पद भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



सुश्री इटियेरा के कार्यकाल में दक्षिण रेलवे ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया तथा नई उंचाईयों को छुआ। इनके कार्यकाल में दक्षिण रेलवे में यात्री सुविधाओं एवं सेवाओं भी काफी प्रगति हुई। महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रूप में सुश्री इटियेरा के कार्यकाल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना एवं यात्री सुविधाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हो सकेंगी। इसके साथ ही साथ देश की आर्थिक प्रगति की ओर भी अधिक बल देने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सकारात्मक योगदान हो सकेगा। सुश्री इटियेरा ने दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल में सहायक परिचालन प्रबंधक के पद से अपनी सेवा की शुरुआत की है। दक्षिण रेलवे के चन्नई मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, उप मुख्य वाणिज्य परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, चेयरमैन, रेलवे भर्ती बोर्ड तिरुवनंतपुरम सहित कई महत्वपूर्ण पदों कार्य किया।

रेणुका सिंह की पहल पर मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू

कोरिया। छत्तीसगढ़ सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के मट्टा, नेऊर, दहियाडांड, दरौटोला, गधौरा और आमादमक में मोबाइल टावर स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में संचार सुविधा न होने के कारण स्थानीय नागरिकों को कई शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। गत विधानसभा चुनाव में मोबाइल नेटवर्क एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था तब ग्रामीणों ने क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर लगाने की मांग की थी। अब विधायक रेणुका सिंह की पहल पर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल टावरों के स्थापना हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।



नेटवर्क की समस्या से निजात मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में आनलाइन इंटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते थे उसमें भी अब आसानी होगी।

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने बताया कि सोनहत विकासखण्ड के रामगढ़ इलाके के एक दर्जन से ज्यादा गांव अब भी मोबाइल नेटवर्क विहीन हैं इन गांवों में भी जल्द ही मोबाइल टावर लगाया जाएगा। रेणुका सिंह ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने रामगढ़ इलाके के कई गांवों में जनसंपर्क किया जहां सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क न होने की आई। क्षेत्र के परिजनों द्वारा बताया गया कि मोबाइल नेटवर्क न होने से उन्हें राशन से लेकर कई सरकारी दस्तावेजों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। रेणुका सिंह ने बताया कि गांवों की समस्या को देखते हुए मेरे द्वारा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पत्राचार कर जल्द ही क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जाएगा।

बिलासपुर में पारा 46 पार गर्मी से फटा फ्रिज
बिलासपुर। पिछले दो दिनों से छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी की चपेट में है राजधानी जहां तप रही है वहीं मंगलवार की रात 10 बजे तक गर्म हवाएं चल रही थी। बुधवार को सुबह बदली थी लेकिन 10 बजे के बाद फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाए शुरू दिये। बुधवार को बिलासपुर जिले में पारा 46 पार कर गया है जहां भीषण गर्मी की वजह से घर में रखे फ्रिज के कम्प्रेसर में अचानक ब्लास्ट हो गया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस हादसे में किसी तरह से पूरा परिवार बाल-बाल बचा। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम को दी। जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में घर का फ्रिज, टीवी और सोफा सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया।

15 मृत व 36 गोवंश मिले जीवित, ट्रक चालक फरार
महासमुंद्र। बसना तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू ने गौ तस्करी पर नकेल कसते हुए एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जहां उन्होंने पलसापाली अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर गाय से भरे ट्रक को जप्त किया जिसमें 15 गायें मृत व 36 गोवंश जीवित मिले। जीवित गौ वंशों को निकटतम गौशाला में रखवाया गया है। वहीं मौके से फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ से ओडिशा को जोड़ने वाली बसना से पदमपुर रोड के अंतिम छोर पर स्थित पलसापाली बेरियर के पास गौ वंशों से भरी हुई एक ट्रक खड़े होने की जानकारी ग्रामीणों ने सुबह दी। जिस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंच कर गाय से लदे ट्रक को जप्त किया गया है। ट्रक में 52 गौ वंश होने की बात सामने आई है जिनमें से 15 मृत तथा 36 गौ वंश जीवित मिले हैं। जीवित गौ वंशों को निकटतम गौशाला में रखा गया है। मौके से ट्रक का चालक फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।

यातायात जागरूकता बाइक हेलमेट रैली का आयोजन
जगदलपुर। जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक के द्वारा बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके लिए रोजाना बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रहा है। इस चेकिंग के दौरान अगर पुलिस जवान भी आ रहे थे तो उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई के साथ ही विभागीय कार्रवाई की जा रही है। शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक बस्तर के नेतृत्व में जिले में पिछले 2 सप्ताहों से सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त एवं सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं, यदि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनके विरुद्ध भी सख्ती से चालाना कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भानपुरी थाना क्षेत्र में बाइक हेलमेट रैली का आयोजन भी किया गया। इस दौरान यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया।

कर्ज देकर मोटी रकम वसूलने वाला सूदखोर गिरफ्तार
कोरबा। कोरबा में लोगों को कर्ज देकर उसके एवज में मोटी रकम वसूलने वाले एक बड़े सूदखोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम इरफान कुरैशी उर्फ मौनू है। आरोपी ने कई सरकारी कर्मचारियों को अपने झांसे में लिया था। इरफान द्वारा लोगों को जरूरत के हिसाब से कर्ज पर पैसे दिया जाता था और उसके एवज में कई गुना मोटी रकम वसूला करता था। आरोपी कर्ज देने के बत एटीएम, पासबुक और चेक रख लेता था ताकी उसकी वसूली समय पर हो सके। इरफान खान पुलिस ने उसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। जिसके पास से 29 से अधिक एटीएम, कई पासबुक, चेक, आधार कार्ड के साथ ही अन्य सामानों की जब्त की है। इरफान के खिलाफ कुसमुंडा थाना में भी सूदखोरी का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि सूदखोरी के पैसों से इरफान ने अकूत संपत्ति जमा कर रखी है जिस शायद भविष्य में कुर्क भी किया जा सकता है।

कपड़े की दुकान में लगी आग, जलकर हुई खाक
जगदलपुर। बुधवार को सुबह शहर के मेन रोड स्थित कपड़ा दुकान में अचानक से धुआं निकलता देख लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आग तेजी से दुकान में फैल गई और दुकान में रखा लाखों रुपये का माल जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची आग बुझाने में जुट गई। दमकल की करीब तीन से अधिक गाड़ियों को मदद ली गई। वहीं, आग की लपट बढ़ते ही जा रही थी। बताया जा रहा है कि शहर के सबसे व्यस्त मार्ग मेन रोड स्थित सावी साड़ी हाउस में बुधवार को सुबह अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण तो पता नहीं चला लेकिन आग काफी तेजी से फैली। आग की लपट दूर तक दिखाई दे रही थी। मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस से लेकर यातायात पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों से लेकर काबाफ दल मौके पर पहुंचा। घंटों तक आग को बुझाने का सिलसिला जारी रहा। इस घटना के दौरान दुकान के पास खड़ी बाइक के साथ ही कार भी जल गई।

बिना खरीद-बिक्री के पटवारी ने जमीन का कर दिया नामांतरण

नगर पंचायत जैजपुर का है यह अनोखा मामला
जैजपुर/सक्ती। जमीन के मामले फर्जीबाड़े का जो खेल चलता है उस पर अंकुश लगाने के लिये जिला प्रशासन सतक रहता है बावजूद इसके इस धंधे पर प्रशासन की नकेल ढीली पड़ जाती है और यही वजह है कि आज भी जनता ठगी जा रही है। जिले में जमीन की खरीद-बिक्री का अनोखा मामला नगर पंचायत जैजपुर का है जहां न तो जमीन बेची गई और न किसी ने खरीदी लेकिन पटवारी रेकार्ड में जमीन का नामांतरण हो गया। जैजपुर तहसील के नगर पंचायत जैजपुर का। जहां पर पटवारी द्वारा 11 मई को जमीन का नामांतरण कर दिया गया। इस मामले में नेतराम श्रीवास सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक जिला सैक्युरिटी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर शाखा जैजपुर को जब अपनी खुद की जमीन को दूसरे व्यक्ति के नाम पर नामांतरण की जानकारी मिली तो उनके होश फाखा हो गये।



जानकारी मुताबिक गांव के सेवानिवृत्त नेतराम श्रीवास ने बताया कि खसरा नम्बर 3251 एवं 2366 रकबा 38 एवं 33 डिसमिल खेत जो पैतृक भूमि है जो राज्यस्व अभिलेख फार्म की 1 और भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक प 561260 में दर्ज चला आ रहा है उक्त भूमि को दिनांक 1/9/75 पटवारी एवं तहसीलदार जैजपुर का हस्ताक्षर सहित शील महर लगा हुआ जारी किया गया है उक्त जमीन की सीमांकन या शिकायत जांच दिनांक 18 जनवरी 24 को पटवारी प्रमोद यादव द्वारा किया गया जिसमे

खसरा नम्बर 3251रकबा 38 डिसमिल एवं खसरा नम्बर 2366 को भूमि को गुलापीबाई पिता गरहन ने अपने भूमि स्वामी हक की जमीन खसरा 3250 एवं 2367 में उक्त जमीन के मेड को काटकर मिला लिया है इस तरह तत्कालीन पटवारी से मिलीभगत कर अवैधानिक रूप से कानून को अपने हाथ में लेकर अपराध किया गया है नेतराम श्रीवास पेशे से सरकारी कर्मचारी थे इसलिए नौकरी कार्यकाल में हमेशा जैजपुर से बाहर रहते थे। अपने पैतृक संपत्ति के खेत मे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाये इसी का लाभ उठाते हुए गुलापी बाई श्रीवास ने पटवारी से साटागांठ कर उक्त जमीन को नामांतरण करा लिया गया है लेकिन मजे की बात तब हुई नामांतरण होने के बावजूद आज पर्यंत तक नेतराम श्रीवास का नाम भी वन पौंचाला से नहीं कटा था लेकिन मामले की जानकारी ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में त्रुटि सुधार की फर्जी आवेदन लगाकर एसडीएम सक्ती से अपने पक्ष में सुनवाई

करवा लिया गया है जो समझ से परे है। नेतराम श्रीवास ने बताया कि मेरे जमीन को कुट्टरचना कर अपने नाम पर नामांतरण करवा लिया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है मेरे द्वारा उक्त जमीन की बिक्री ही नहीं की गई तो कैसे किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम पर नामांतरण किया जाना समझ से परे है। जैजपुर पटवारी प्रमोद यादव ने कहा रिकार्ड के अनुसार सत्र 1997 में खसरा का नामांतरण हो चुका था नेतराम श्रीवास के नाम पर जमीन का खसरा रिकार्ड में था तो गुलापीबाई ने त्रुटि सुधार के लिए एसडीएम दिया गया था। मैंने एसडीएम सक्ती के आदेश का पालन करते हुए रिकार्ड में गुलापीबाई के नाम पर किया था सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक नेतराम श्रीवास ने कहा मैंने उक्त जमीन की बिक्री किसी को नहीं की उसके बावजूद गुलापीबाई के नाम पर नामांतरण पटवारी द्वारा किया गया है इसकी शिकायत थाना जैजपुर में कर्हूंगा।

सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता से संपर्क किया। अरविंद गुप्ता ने अनुज्ञा पत्र जारी करने के एवज में 8 हजार रुपये रिश्तत की मांग की। रविशंकर गुप्ता ने इसकी शिकायत आवश्यक प्रमाणों के साथ एंटी करण ब्यूरो से कर दी। शिकायत के सत्यापन के बाद उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। आरोपी अरविंद गुप्ता ने शिकायतकर्ता रविशंकर को रुपये के साथ बिलासपुर के व्यापार विहार में बुलाया था। जैसे ही यहां रविशंकर से अरविंद गुप्ता ने 8 हजार रुपये लिए एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

गंगा से कावेरी तक दक्षिण की चुनावी यात्रा

मधुरेंद्र सिन्हा

भारतीय जनता पार्टी के आलोचक उसे 'काऊ बेल्ट' की पार्टी कहकर उपहास करते रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी एक लहर के साथ केंद्रीय राजनीति में आये, तो भी देश के दक्षिणी हिस्से (कर्नाटक छोड़कर) में भाजपा लगभग अनुपस्थित थी। साल 2019 में पार्टी दुबारा सत्ता में आयी, लेकिन उसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की अपनी थोड़ी सी सीटें भी गंवा दी। केरल में पार्टी का खाता पहले की ही तरह नहीं खुला। इन अनुभवों से सबक लेते हुए भाजपा ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी। अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्हें संभालना का गहरा अनुभव है, दक्षिण में अपने पैर मजबूत करने शुरू कर दिये। इस दिशा में उन्होंने तमिलनाडु में पूर्व पुलिस अधिकारी कुपुसामी अन्नामलाई को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया। हालाँकि सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक ने उनका विरोध किया फिर भी गृह मंत्री झुके नहीं और उसके बाद जो हुआ, उसे सबने देखा। भाजपा ने तमिलनाडु में एक तूफान ला दिया और द्रमुक को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। तमिलनाडु, जहाँ लोकसभा की 39 सीटें हैं, में इस बार पार्टी की शक्ति साफ दिखी। रणनीति बनाने में सिद्धहस्त अमित शाह ने अन्नामलाई को पूरी आजादी दी, जिसका नतीजा था कि वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दौरा अब तक का सबसे प्रभावशाली था। पूरे राज्य में भाजपा की उपस्थिति साफ दिखने लगी और चुनाव में इसका असर पड़ा। इसके पहले राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह से तमिलनाडु को महत्व दिया गया, वह वहाँ के लोगों को खूब भाया। आंध्र प्रदेश में भी पार्टी ने नये सिरे से पार्टी को संगठित किया और राजनीति के पुराने खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ ले लिया। साथ ही, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण को भी अपना सहयोगी बनाया। यह एक रणनीतिक फैसला था, जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे। इस गठबंधन ने मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को हिलाकर रख दिया और उन्होंने जनता के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। अब वह बात सच साबित हो जाती है और ओवैसी बंधुओं की नौद लड़ा दी है। पार्टी ने दक्षिण भारत के लिए इस बार ठोस रणनीति बनायी और उसे कार्यान्वित भी किया। हर राज्य में स्थानीय नेताओं को पूरा महत्व देकर उन्हें संसाधनों के साथ आगे बढ़ाया गया, जो कारण रहा। केरल में भी एनडीए को बढ़िया रिस्पांस मिला है। इस कारण कहा जा रहा था कि इस बार न केवल हिंदू वोटर, बल्कि ईसाई भी उसे वोट देंगे। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने से स्थिति में बदलाव हुआ है। कांग्रेस के कमजोर पड़ने का फायदा भी उसे साफ तौर पर मिलता दिख रहा है। भाजपा के केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्र अमित शाह की बनायी हुई रणनीति को लागू करने में सफल रहे हैं। सभी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भाजपा केरल में तीसरी शक्ति बन गयी है और उसका वोट प्रतिशत दहाई अंकों में होगा। अगर यह बात सच साबित हो जाती है कि पार्टी इस राज्य में पांच सीटें तक ला सकती है, तो यह उसके हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी होने का ठप्पा सदा के लिए मिटा देगी। भाजपा ने बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली बार भी चुनाव की कमान संभाली थी और इस बार भी वे काफी सक्रिय रहे हैं। बंगाल के हर मुँह पर उन्होंने ध्यान रखा और केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से वहाँ के अपराधी मिजाज के तुणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों को धूल चटा दी। संदेशखाली कांड में जिस शाहजहां शेख नाम के डॉन का नाम आ रहा था, वह अब सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में है। इस घटना पर भाजपा ने जिस तरीके की सक्रियता दिखायी, उससे वहाँ के वोटों को हिम्मत मिली। अब ऐसा दिखता है कि वहाँ पासा पलट गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में तुणमूल के कई नेता जेल जा चुके हैं। इससे पार्टी के प्रति जनता में पहले जैसा जुड़ाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर की बात में दम लगता है कि बंगाल में भाजपा दूसरे नंबर पर तो रहेगी ही, पहले स्थान पर भी आ सकती है।

संदीप अग्रवाल

शनिवार को लोकसभा चुनावों का छठवां चरण सम्पन्न हुआ। जैसी कि अपेक्षा थी, इस बार भी कुल मतदान प्रतिशत साठ के आसपास ही रहा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं वाले देश में यह बात हैरान कर सकती है कि यहाँ करीब एक तिहाई मतदाता तो वोट डालते ही नहीं। इन आम चुनावों में मतदान न करने वालों की संख्या और प्रतिशत बढ़ गया है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसके कारणों और उपचार पर विचार बहुत आवश्यक है। वरना यह प्रतिशत आगे भी घटता जाएगा। ऐसे में सरकारें तो बनेंगी, लेकिन उनमें जनता की पसंद से ज्यादा उदासीनता का हाथ होगा।

इसलिए पहले उन कारणों पर विचार करना भी जरूरी है जो मतदाताओं को दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव में भागीदारी को लेकर हतोत्साहित करते हैं। हमारे यहाँ जितने वोटर हैं, उतनी तो अधिकतर देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं है। फिर भी यह सैलाब मतदान केंद्रों पर क्यों नजर नहीं आता विश्लेषक अलग-अलग तरीकों से इस प्रश्न का उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है कि इस बार रिकॉर्डतोड़ गर्मी की वजह से मतदान में कमी आयी, जबकि गर्मी तो पश्चिम बंगाल में भी थी, वहाँ तो मतदान प्रतिशत लगातार देश में सबसे ज्यादा रहा है। उड़ीसा में भी रिकॉर्डतोड़ गर्मी है लेकिन वहाँ भी मतदान का प्रतिशत अन्य राज्यों से बेहतर है। बेशक, गर्मी एक कारण हो सकती है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं हो सकती।

भारत दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है, यहाँ साल का तीन चौथाई भाग गर्म या गर्मी जैसे माहौल में ही गुजरते हैं। क्या अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वे एक दिन भी असुविधा नहीं सह सकते क्या वे अपनी व्यक्तिगत पसंद और प्राथमिकताओं को कुछ घंटे के लिए स्थगित नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि उनके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उन्हें वोट डालना ही है। और भी कई व्यावहारिक कारण हैं, जो हमारे देश में मतदाता को इस उदासीनता के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। जैसे कि मतदाताओं में जागरूकता का



अभाव, जिसके चलते वह मतदान के महत्व और मतदान न करने के परिणाम के बारे में नहीं सोच पाता। दूसरा कारण विस्थापन हो सकता है। बड़ी संख्या में लोग काम के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ दूसरे स्थानों पर रहते हैं और सिर्फ मतदान के लिए वापस आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता।

इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में, चुनावी हिंसा, धमकी या राजनीतिक अशांति का डर भी लोगों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से हतोत्साहित कर सकता है। कुछ हद तक, वोटर लिस्ट में होने वाली गड़बड़ियाँ और बूथ पर नजर आने वाली बेइंतजामी को भी दोष दिया जा सकता है। लेकिन, देश भर में लाखों बूथों पर मतदान होता है, कुछेक जगह पर गड़बड़ हो सकती है, मतदाता सूची से नाम गायब हो सकते हैं, लेकिन यह मतदान न करने का बहाना तो नहीं बन सकता।

कुछ विचारक यह तर्क देते हैं कि जनता का राजनेताओं और राजनीतिक दलों से मोहभंग हो रहा है। जिस तरह से अधिकतर उम्मीदवार जीतने के बाद अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना तो दूर सुध तक लेते नजर नहीं आते, उसे देखते हुए मतदाताओं में अरुचि होना स्वाभाविक है। उनकी इस बढ़ती बेरुखी का एक कारण कुछ जन प्रतिनिधियों का विजयोपरांत भ्रष्ट आचरण भी है। इसके चलते चुनावी प्रक्रिया में लोगों की रुचि कम हो रही है और वे मतदान को समय की बर्बादी मानते हैं।

लोकतंत्र में मतदाताओं के घटते विश्वास और रुचि का कमोवेश यही मंजर यूके, कनाडा, यूएस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी देखने को मिलता है, जहाँ पिछले आम चुनावों में क्रमशः 67व व 66व मतदान दर्ज किया गया। लेकिन, वहाँ फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और आस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं, जहाँ 74, 77, 79 व 92 प्रतिशत मतदान हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें सिर्फ आस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है, जहाँ मतदान अनिवार्य है। 1924 से यहाँ मतदान न करने पर जुर्माना का प्रावधान है। हो सकता है कि यहाँ इतने ज्यादा मतदान प्रतिशत के पीछे यह भी एक कारण हो।

इसके अलावा उरुगे और लज्जमबर्ग जैसे देश भी मतदान न करने वाले नागरिकों पर जुर्माना लगाते हैं। लेकिन, कुछ अन्य देश हैं, जो इस मामले में ज्यादा सख्त हैं। जैसे बेल्जियम में जुर्माना लगाने के अलावा मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, इक्वाडोर में सरकारी दस्तावेज हासिल करने में परेशानी का सामना कर पड़ सकता है, पेरू में कुछ समय के लिए नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।

कुछ लोग भारत में भी इसी सख्ती की कवालात करते हैं। लेकिन, आस्ट्रेलिया के अलावा उपरोक्त सभी देशों का अनुभव बताता है कि सख्ती से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अधिक से अधिक दस-पंद्रह फीसदी मतदान और बढ़ जाएगा।

दरअसल सख्ती से ज्यादा जरूरत है, मतदाताओं को यह समझाने की कि उनका वोट न डालना स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता। हालात बेहतर होंगे, उनके वोट से। अधिकतर, हम देखते हैं कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह की कवायदें करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य बस यही होता है कि वे उनके पक्ष में मतदान करें। वे यह कभी नहीं सोचते कि बूथ तक जाने या वहाँ अपनी बारी का इंतजार करने से मत डालने तक उन्हें किस तरह की असुविधा होती है और उससे कैसे बचा जाए। जैसे कि लंबी कतारें, इसका एक उदाहरण है।

प्रतिकूल मौसम में कतार में लगना बहुत असुविधाजनक होता है। इस समस्या को पंजाब में समझा गया और मतदाताओं के लिए मतदाता कतार सूचना प्रणाली लॉन्च की गई। अब एक जून को होने जा रहे अंतिम चरण के मतदान के दौरान मतदाता घर बैठे देख सकते हैं कि किस बूथ पर कितनी लंबी कतार है। इससे वे अपना प्रतीक्षा समय कम कर सकते हैं और देर तक कतार में लगे रहने की परेशानी से बच सकते हैं। इसके अलावा, उनके लिए पंखे, कूलर, छाँह के लिए शेड, ठंडे पानी और बैटने की व्यवस्था की जाएगी। यह एक छोटी सी, मगर महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे और भी कई कदम उठाए जा सकते हैं।

इस दृष्टि से वन नेशन, वन इलेक्शन का विचार भी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन, हालात बदलने के लिए अकेला यही काफी नहीं है। समाज के सभी वर्गों में सत्ता और व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करना, सभी के हित सुनिश्चित करना और उन्हें मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित अभियान चलाना जैसे कुछ उपाय भी मतदान प्रतिशत बढ़ान में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कानूनी रूप से मतदान अनिवार्य करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन, इससे पहले जरूरी है कि सभी को यह सुविधा मिले कि वे जहाँ हैं, वहाँ रहते हुए मतदान कर सकें। तकनीकी को अपनायने से यह संभव हो सकता है। ब्लॉकचेन टेकनॉलॉजी को अपनाकर लोगों को उनके मोबाइल या कम्प्यूटर से मतदान की सुविधा दी जा सकती है और यूनिफ आईडी के इस्तेमाल से दोहरे मतदान को भी रोका जा सकता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामणि उपनिषद् (भाग-15)

गतांक से आगे...

इसी प्रकार धारणा की द्वादश आवृत्ति पर ध्यान बनता है तथा द्वादश बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा योग के विशारदों का मत है। समाधि की स्थिति में साधक परमप्रकाशरूप अनन्त विश्वतोमुख अर्थात् सर्वत्र समभाव प्राप्त कर लेता है, इस स्थिति को प्राप्त होने पर न तो कुछ करना शेष रहता है, न किये हुए कर्म मनुष्य को बन्धन में डालते हैं, इससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है।



दोनों पैर की पंढियों को मेढ़ू अर्थात् सीवन स्थान में लगाकर आसन में दृढ़तापूर्वक बैठे, तत्पश्चात् आँख, कान एवं नाक को अँगुलियों से बन्द करे और मुँह से वायु खींचे। पुनः नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए, फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश

में रोके। पुनः ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थिर करके मन को उसी में लगाए, इस क्रिया से योगियों को विशेष समत्वभाव प्राप्त होता है। ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाशमण्डल (हृदय प्रदेश) में स्थिर होती है, तब साधक को महान् ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, षष्ठा आदि वाद्यों की तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा नादयोग की सिद्धि होती है। विधिवत् प्राणायाम के अन्त्यस से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम के न करने से यह शरीर रोगों का उत्पत्तिस्थान बना रहता है। वायु के विकृत होने के कारण ही खाँसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आँख की पीड़ा होती है और नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं।

क्रमशः ...



हिंदी पत्रकारिता दिवस



30 मई को मनाया जाता है। प्रथम हिन्दी समाचार पत्र के प्रकाशक पं. जुगल किशोर मूलतः कानपुर के निवासी थे। वे सिविल एवं राजस्व उच्च न्यायालय कलकत्ता में पहले कार्यवाहक रीडर तथा बाद में वकील बन गए। राजा शिवप्रसाद के नेतृत्व में 1845 में काशी से हिन्दी पत्र 'बनारस अखबार' का प्रकाशन हुआ, गोविन्द रघुनाथ इसके संपादक रहे। 1854 में हिन्दी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र 'समाचार सुधावर्षण' का प्रकाशन भी कलकत्ता से हुआ, बाबू श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में यह पत्र प्रकाशित हुआ। हिन्दी का एक और प्रमुख पत्र 'कविचचनसुधा' का प्रकाशन भारतेन्दु हरीशचंद्र ने काशी से किया। 1907 में 'अभ्युदय' पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रयागराज (इलाहबाद) से मालवीय ने किया। 1910 में हिन्दी का एक

'30 मई' को मनाया जाता है। प्रथम हिन्दी समाचार पत्र के प्रकाशक पं. जुगल किशोर मूलतः कानपुर के निवासी थे। वे सिविल एवं राजस्व उच्च न्यायालय कलकत्ता में पहले कार्यवाहक रीडर तथा बाद में वकील बन गए। राजा शिवप्रसाद के नेतृत्व में 1845 में काशी से हिन्दी पत्र 'बनारस अखबार' का प्रकाशन हुआ, गोविन्द रघुनाथ इसके संपादक रहे। 1854 में हिन्दी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र 'समाचार सुधावर्षण' का प्रकाशन भी कलकत्ता से हुआ, बाबू श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में यह पत्र प्रकाशित हुआ। हिन्दी का एक और प्रमुख पत्र 'कविचचनसुधा' का प्रकाशन भारतेन्दु हरीशचंद्र ने काशी से किया। 1907 में 'अभ्युदय' पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रयागराज (इलाहबाद) से मालवीय ने किया। 1910 में हिन्दी का एक

प्रमुख पत्र 'मर्यादा मासिक' का प्रकाशन कृष्णकांत मालवीय ने किया। कालांतर में हिन्दी के कई पत्र निकले परंतु खण्डवा से 'प्रभा' (1913) माखनलाल चतुर्वेदी कानपुर से 'प्रताप' (1913) गणेश शंकर विद्याधी, 1902 'समालोचक' जयपुर से चंद्रधर शर्मा तथा 1909 'इंदु काशी' (बनारस) अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित किए गए। 1920 में गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। भारतीय इतिहास में 1920 से 1947 का समय गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 से 1947 तक की भारतीय पत्रकारिता के अधिकांश समाचार पत्र स्वतंत्रता आंदोलन के रंग में रंगे थे। 1920 में काशी बनारस से प्रकाशित समाचार पत्र 'आज' का भारतीय पत्रकारिता में अपना अलग स्थान है। 5 अप्रैल 1920 को इसका प्रकाशन शिवप्रसाद गुप्त ने किया था।

हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विशेष

प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी

हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते समय हम सबलों से घिरे हैं और जवाब नदारद हैं। पं.जुगलकिशोर शुक्ल ने जब 30 मई, 1826 को कोलकाता से उदंत मार्तण्ड की शुरुआत की तो अपने प्रथम संपादकीय में अपनी पत्रकारिता का उद्देश्य लिखते हुए शीर्षक दिया - हिंदुस्तानियों के हित के हेतु। यही हमारी पत्रकारिता का मूल्य हमारे पुरखों ने तय किया था। आखिर क्यों हम पर इन दिनों सबालिया निशान लग रहे हैं। हम भटके हैं या समाज बदल गया है?

कुछ दिनों पहले दिनों, देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि किसी देश को लोकतांत्रिक रहना है, तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। जब प्रेस को काम करने से रोका जाता है, तो लोकतंत्र की जीवन्तता से समझौता होता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश, ऐसा कहने वाली पहली विभूति नहीं हैं। उनसे पहले भी कई बार कई प्रमुख हस्तियां प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर मिलते-जुलते विचार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर चुकी हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है, तो वह अकारण नहीं है। उसने समय-समय पर लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए बहुत काम किया है और इसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई है। इसके बदले उसे समाज का, लोगों का भरपूर विश्वास और सम्मान भी हासिल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से बीते दो-तीन दशकों में यह विश्वास लगातार दरकता गया है, सम्मान घटता गया है।

मीडिया की इस घटती प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के पीछे बहुत सारे कारण गिनाये जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि उदारीकरण की आंधी से पहले जिस मीडिया ने खुद को एक मिशन बनाए रखा था, उसने व्यावसायिकता को चकमाँच



में बहुत तेजी से अपना 'कॉर्पोराइजेशन' कर लिया और खुद को 'मिशन' की बजाए खालिस 'प्रोफेशन' बना लिया। अब जब यह प्रोफेशन बना तो इसकी प्राथमिकताएं भी बदल गईं। 'जन' की जगह 'धन' साध्य बन गया। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मीडिया प्रतिष्ठानों ने अपने तौर-तरीके पूरी तरह बदल लिए। 'कंटेंट' की बजाय उन्होंने 'आइटम' पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि रीडरशिप और टीआरपी में ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा जा सके। जितनी ज्यादा ऊंचाई, उतना ज्यादा विज्ञापन राजस्व। उसमें भी भारी घालमेल। अधिकतर अखबार और टीवी चैनल, सामग्री की गुणवत्ता की बजाए आंकड़ों की बाजीगरी में अधिक भरोसा करने लगे। लेकिन, या तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर परवाह नहीं की, कि इस पूरे चक्र में वे समाज और लोगों का भरोसा खो रहे हैं।

अब स्थिति यह है कि मीडिया तो लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन लोगों में उसकी विश्वसनीयता लगातार कम हो रही है। आज मीडिया के बहुत सारे रूप हैं। मनोरंजन को छोड़ दीजिए, तो रेडियो ज्यादा लोग सुनते नहीं, टीवी देखते नहीं, अखबार पढ़ते नहीं-अगर यह सब करते भी हैं, तो वे माध्यम उनके मन में कोई सकारात्मकता जगा पाते

डॉ. अलीम अहमद खान

'खींचो न कमानों को न तलवार निकालो । जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो ।।

अकबर इलाहाबादी का यह शेर पत्रकारिता की ताकत बताने के लिए काफी है। 30 मई 2024 को भारतीय हिन्दी पत्रकारिता 198 वर्षों की हो जाएगी। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अपना अलग महत्व रखने वाला समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र, 30 मई 1826 को कलकत्ता से साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ, इसका प्रकाशन जुगल किशोर शुक्ल ने किया। इस समाचार पत्र के अंक हिन्दी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा के मिश्रण में प्रकाशित होते थे। इसके प्रथम अंक की 500 प्रतियां प्रकाशित की गईं, यह समाचार पत्र प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता

...

हिन्दी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष

मीडिया: दरकते भरोसे को बचाएं कैसे

में सफल नहीं हो पाते। जबकि कालांतर में ऐसे असंख्य अवसर आए हैं, जब मीडिया ने अपने सामाजिक और लोकतांत्रिक दायित्वों का भली-भांति निर्वहन किया है। विश्वसनीयता के मामले में पत्रकारिता को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, 21 वीं सदी के आरंभ से पहले की पत्रकारिता और दूसरी इसके बाद की पत्रकारिता। पहले वर्ग में वह पत्रकारिता आती है जो समाज के लिए जयप्रकाश नाशयण और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे जनकों को मजबूती प्रदान करती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती थी, जनहित के लिए सत्ता की नाक में दम किए रहती थी। दूसरी पत्रकारिता वर्ष 2000 से बाद की पत्रकारिता है, जिसमें सनसनी है, स्टिंग हैं, मीडिया ट्रायल हैं, टीआरपी है, प्रायोजित यात्राएं हैं, निहित स्वार्थ हैं। अगर कुछ नहीं है, तो समाज का विश्वास। अब कोई मीडिया की ओर नहीं देखता। लोग उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, उस पर भरोसा नहीं करते। उनके लिए मीडिया पर प्रसारित सामग्री मनोरंजन की चीज बन चुकी है। हालाँकि अखबार अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ इसी राह पर रहे हैं।

इसकी दूसरी वजह पिछले दस-पंद्रह सालों में वैकल्पिक मीडिया, या डिजिटल मीडिया, का दिनोंदिन फैलता फलक हो सकती है। वैकल्पिक मीडिया ने, आम लोगों को अपनी बात सामने रखने की ऐसी सहूलियत प्रदान की है, जिसने पारंपरिक संचार माध्यमों पर उनकी निर्भरता खत्म कर दी है। अब वे अपनी समस्याएं या चिंताएं लेकर अखबारों-टीवी चैनलों के चक्कर नहीं काटते, बल्कि फेसबुक या ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। क्योंकि इनमें उन्हें भरोसा रहता है कि अब उनकी बात बिना किसी बाधा या समस्या के उन तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी, जिन तक पहुंचनी चाहिए। तीसरी वजह, खुद वह समाज है जो मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी

ठीक से न निभाने का दोषारोपण तो करता है, लेकिन कभी किसी संकट के समय उसके साथ खड़ा नजर नहीं आता। 'रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स' के मुताबिक वर्ष 2003 से 2022 तक, दो दशकों के दौरान दुनिया भर में 1668 पत्रकारों की हत्या हुई। यानि हर साल करीब 84 पत्रकार। इसके अलावा 'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल एक दिसंबर तक 363 पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। 'रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स' की रिपोर्ट इनकी संख्या 533 बताती है। उनकी ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में पिछले साल 65 पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को बंधक बनाकर रखा गया और 49 लापता हैं।

अब आप याद कीजिए कि क्या कहीं आपने किसी देश, शहर या समाज में लोगों को इस बात के लिए इकट्ठा होकर कोई सामाजिक आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते देखा है कि अमुक पत्रकार को जेल से रिहा किया जाए, या अमुक पत्रकार के हत्यादों को गिरफ्तार किया जाए या अमुक पत्रकार, जिसका असें से कोई अता-पता नहीं है, उसका पता लगाया जाए। और तो और, जिन लोगों के हित के लिए पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डाली है, समाज उनके परिवार की मदद के लिए भी कभी खड़ा नजर नहीं आता। वही समाज जो पानी न आने पर सड़कें जाम कर देता है, किसी सैनिक के शहीद होने पर श्रद्धांजलि यात्राएं निकालता है। अपने अधिकारों के लिए या अपने शहीदों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर आना कदाई गलत नहीं है और न ही यहाँ इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि कहने का आशय यह है कि एक पत्रकार जब अपना फर्ज निभाते हुए मारा जाता है तो उसकी शहादत, उस समाज से भी बदले में कुछ चाहती है, जिसके लिए वह शहादत दी गई। बजाय इसके, हम उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं या उस पर हमले को जायज साबित करने की कोशिश करते हैं।

आज का इतिहास

- 1942 द्वितीय विश्व युद्ध एक हजार ब्रिटिश हमलावरों ने कोलोन, जर्मनी पर 90 मिनट का हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा 262 अलग-अलग हवाई हमलों में जर्मन शहर कोलोन में बमबारी की गई थी।
- 1948 कोलंबिया नदी को पकड़ने वाली एक खाई टूट गई, जिससे बाढ़ आई जिसने वनपोंट, ओरेगन, अमेरिका को नष्ट कर दिया, इसके निर्माण के केवल पांच साल बाद।
- 1959 न्यूजीलैंड के पूर्व नॉर्थ शोर शहर के ऑकलैंडविथ नॉर्थकोट में सेंट मेरीज बे में शामिल होने वाला ऑकलैंड हार्बर ब्रिज, खुल गया।
- 1961 डोमिनिकन स्ट्रॉन राफेल टूरुजिलो को जनरलों के एक समूह ने घात लगाकर हत्या कर दी थी।
- 1962 चिली में 1962 का फीफा विश्व कप की शुरुआत हुआ।
- 1963 बौद्ध संकट-एक समर्थक कैथोलिक भेदभाव के खिलाफ दक्षिण वियतनाम के नेशनल असेंबली के बाहर आयोजित किया गया था, राष्ट्रपति नेगो दीन्ह दीम के खिलाफ पहला खुला प्रदर्शन।
- 1963 बौद्ध संकट दक्षिण-वियतनाम की नेशनल असेंबली के बाहर कैथोलिक भेदभाव के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, राष्ट्रपति एनगो दीन्ह दीम के खिलाफ पहला दर्शन।
- 1966 सर्वेयर 1 का प्रक्षेपण, एक अलौकिक निकाय पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान। सर्वेयर 1 राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका) के मानव रहित सर्वेयर कार्यक्रम में पहला चंद्र नरम-लैंडर था।
- 1967 चुक्उमेमेका ओडुमवु ओजुकु ने दक्षिणपूर्वी नाइजीरिया में एक अलगाववादी राज्य बियाफ्रा की स्थापना की घोषणा की, एक सप्ताह बाद नाइजीरियाई गृहयुद्ध शुरू हो गया।
- 1971 मेरिनर प्रोग्राम : मेरिनर 9 को सतह के 70व नक्शे के लिए, और मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह में अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- 1972 जापानी रेड आर्मी के सदस्यों ने इजरायल के तेल अवीव में लोद एअरपोर्टमेंसरे को लोकप्रिय मोर्चे की ओर से फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए किया, जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 80 अन्य घायल हो गए।
- 1975 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गठन हुआ।
- 1998 उत्तरी अफगानिस्तान में आये भीषण भूकंप में 5000 लोगों की मौत हुई।

हिमाचल में लोकसभा से ज्यादा विधानसभा उपचुनाव की चर्चा

समीर चौगांवकर

हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर भी मतदान होने जा रहा है। छोटे से राज्य की इतनी अधिक विधानसभा सीटों पर मतदान इसलिए हो रहा है कि कुछ माह पूर्व हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट देकर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया था।

बाद में स्पीकर ने इन सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के सभी बागी विधायक भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। इनकी जीत हार से ही सुक्यू सरकार के भविष्य का फैसला होगा।

लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल की मंडी सीट सबसे हॉट और देश भर में चर्चा में रहने वाली सीट बन गई है। इसका कारण यह है कि भाजपा ने यहां से अभिनेत्री कंगना राणावत को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिमाचल की सभी 4 सीटें हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला जीती थी लेकिन मंडी से भाजपा सांसद रहे राम स्वरूप शर्मा का निधन होने के कारण हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने यह सीट जीत ली थी।

प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। इस बार प्रतिभा सिंह ने मंडी से खुद चुनाव न लड़कर अपने बेटे और सुक्यू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतार है। मंडी सीट पर कटौती टकर है। प्रधानमंत्री मोदी कंगना राणावत के लिए रैली कर चुके हैं। मोदी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के

मजबूत संगठन और प्रतिभा सिंह एवं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्यू में सार्वजनिक हो चुके मतभेदों के बाद कांग्रेस के लिए मंडी की राह आसान नहीं है।

कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके मंत्री बेटे विक्रमादित्य के खुले विरोध के बाद बड़ी मुश्किल से कुर्सी बचा सके मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्यू भले ही विक्रमादित्य का प्रचार कर रहे हों लेकिन अंदर से वह विक्रमादित्य की हार से प्रतिभा सिंह को कमजोर देखना चाहते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपनी सीट से लड़ रहे अपने बेटे विक्रमादित्य की हर हाल में जीत देखना चाहती है। कांग्रेस जैसा गुटायी संघर्ष भाजपा में भी मंडी सीट पर दिख रहा है। कई दिग्गज नेताओं की दावेदारी को किनारे कर सिधे कंगना राणावत को टिकट देने के भाजपा हाईकमान के फैसले का मंडी में अंदरूनी विरोध भी जमकर हो रहा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों विरोधी से ज्यादा आपसी भितरघात से परेशान है।

मंडी सीट पर जितना जोर भाजपा को लगाना पड़ रहा है, उतनी ही आसान हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट भाजपा के लिए दिख रही है। राजपूत बाहुल्य हमीरपुर सीट से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राजपूतों को टिकट दिया है। राजपूत वोट दोनों में बंटना तय है, ऐसे में हार जीत का फैसला करने में 3.23 लाख अनुसूचित जाति के वोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्यू और उपमुख्यमंत्री अगिनहोत्री का गृह क्षेत्र हमीरपुर ही है। ऐसे में सुक्यू की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी होने के कारण सुक्यू बचा लगातार प्रचार कर रहे हैं।

हमीरपुर से मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर इस सीट से लगातार तीन बार 2009, 2014 और 2019 में जीत चुके हैं और चौथी बार भी उनके लिए कोई चुनौती



नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के सतपाल रायजादा के लिए राह मुश्किल है। अनुराग से पहले उनके पिता प्रेम कुमार धूमल इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

हिमाचल में जिन छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें से चार सीटें इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आती हैं। 17 विधानसभा सीटों वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के दस, भाजपा के पांच और दो निर्दलीय विधायक जीते थे। लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में दो निर्दलीय और चार कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सुक्यू सरकार रहेगी या जाएगी इसका निर्णय इसी हमीरपुर लोकसभा के साथ होने जा रहे छह विधानसभा उपचुनाव से तय होगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाली नादौन सीट से और उपमुख्यमंत्री हरोली सीट से विधायक हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी हमीरपुर लोकसभा सीट के साथ-साथ यहां

की चार सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव से भी जुड़ी है। हमीरपुर के अंदर आने वाली चार सीटें सुक्यू सरकार के भाग्य का फैसला करेगी।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित शिमला सीट पर भाजपा से विरोध कश्यप और कांग्रेस से सुनोद सुल्तानपुरी मैदान में हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे विनोद सुल्तानपुरी के पिता कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी छह बार सांसद रह चुके हैं। उसके बाद भी कांग्रेस के लिए यह सीट आसान नहीं है। भाजपा के सुरेश कश्यप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शिमला सीट में सोलन, शिमला और सिरमौर जिले आते हैं। शिमला लोकसभा में आने वाली 17 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। उसके बाद भी यह सीट कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रही है।

कांगड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का मुकाबला भाजपा के डॉ राजीव भारद्वाज से है। यह सीट भाजपा का मजबूत गढ़ बन चुकी है। पिछले नौ चुनाव में भाजपा यहां सात बार जीत चुकी है और पिछले तीन चुनाव से भाजपा यहां से लगातार जीत रही है। राजपूत, ब्राम्हण, ओबीसी और एससी मतदाता यहां प्रभावशाली हैं। ब्राम्हण मतदाता कुल मतदाताओं का 20 फीसदी है।

2019 में कांगड़ा से सांसद थे। किसन कपूर को 72 फीसद से अधिक वोट मिले थे। उसके बाद भी भाजपा

ने उनका टिकट काट दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां बेहतर प्रदर्शन किया था और कांगड़ा जिले की 10 विधानसभा सीटें जीती थीं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 11 पर कांग्रेस और 5 पर भाजपा के विधायक हैं। एक धर्मशाला सीट पर विधानसभा चुनाव भी होना है।

मनमोहन सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा ने 1982 में हिमाचल से विधानसभा चुनाव हारने के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा था और अब 42 साल बाद कांगड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के राजीव भारद्वाज भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

2019 में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा 69.7 फीसद वोट मिले थे। कांग्रेस को सिर्फ 27.30 फीसद वोट मिले थे। ऐसे में इस बार वोटों में दोगुने से ज्यादा का अंतर पाटना कांग्रेस के लिए संभव नहीं लगता। सरकार पहले ही डॉंबाडोल स्थिति में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्यू लोकसभा में कांग्रेस की जीत से ज्यादा विधानसभा की छह सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री को मालूम है कि वह लोकसभा की सभी चार सीटें हार जाएं लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में सभी छह सीटें जीत जाते हैं तो वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चार सीटों के साथ साथ विधानसभा की छह सीटें भी जीत कर केन्द्र में और प्रदेश में भी भाजपा को सरकार बनाने की कोशिश में है। ऐसे में हिमाचल का यह लोकसभा चुनाव प्रदेश सरकार का भी भविष्य तय करेगा। हिमाचल में कांग्रेस सरकार रहती है या भाजपा आती है, इसका फैसला 4 जून को होगा।

राजनीति का लालू मॉडल प्रिय है रोहिणी को

चेतनादित्य आलोक

लोकसभा चुनाव 2024 जैसे-जैसे समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे और अधिक रोमांचक होता जा रहा है। चुनाव आयोग की चिंता और कोशिश इस बात को लेकर नित्य-निरंतर जारी है कि लोकसभा चुनाव के सात चरणों के बेहद लंबे, लेंदी एवं उबाऊ शिड्यूल को वह शांतिपूर्णक एवं निर्विघ्न निपटा सके। बहरहाल, बिहार की बात करें तो राज्य की चुनावी फिजा में लालू मॉडल राजनीति का दबदबा आज भी कायम है। वैसे बिहार का 1990 से 2005 के बीच का वह राजनीतिक दौर नहीं भूला जा सकता, जब लालू यादव मतपेटी से जिन निकालने का दावा करते थे। वे हकड़कर कहते थे कि मतगणना के दिन मतपेटी से जिन निकलेगा और लालू चुनाव जीत जाएगा। हालांकि इसका आज तक पता नहीं लग पाया है कि वह तथाकथित जिन्न प्रत्याशियों को चुनाव जिताने में कितना सहायक अथवा कारगर था। पता तो आज तक यह भी नहीं चल पाया है कि वह जिन्न स्वयं लालू यादव को कितनी बार चुनाव जिताने में सफल रहा था। बता दें कि रोहिणी की शादी के समय पटना में नए खुले गाड़ियों के शोरूम से लगभग 45 नई कारें जबरदस्ती उठा ली गई थीं। दर्जन भर दुकानों से लगभग 100 सोफा-सेट तथा अन्य फर्नीचर लाए गए थे। एक शोरूम से 07 लाख रुपए के डिजाइनर कपड़े उठा लिए गए थे और 50 किलो ड्राईफ्रूट्स के अलावा खाने-पीने की अन्य सामग्रियां भी लूट ली गई थीं। बताया जाता है कि इसी कारण से पटना के एक्जिबिशन रोड पर गाड़ियों के दो शोरूम बंद कर दिए गए थे और कुछ दिनों बाद टाटा कंपनी ने भी अपने शोरूम में ताला लगा दिया था। तब पटना में लालू यादव के सालों सुभाष और साधु यादव का दबदबा कायम था। इसका तात्पर्य यह है कि आजकल राजनीति में प्रायः सबकुछ केवल लाभ और हानि को देखकर ही निर्धारित किया जाने लगा है। बहरहाल, लालू यादव ने बिहार की चुनावी भूमि में जिन तिकड़मबाजियों और चालबाजियों का बीजारोपण किया था, उसकी फसल आजकल उनकी संतानें काटने लगी हैं। तेज प्रताप के कारनामों से तो सभी परिचित ही हैं कि कैसे जब भी वे मुंह खोलते हैं या कुछ राजनीतिक पहल करते हैं तो बेलगाम हो जाते हैं। अपनी इस बेलगामी के कारण वे अपनी तथा अपने दल की किरकिरी कर बैठ कर चुके हैं। हालांकि उनके छोटे भाई तेजस्वी की कुछ सधी चालें बताती हैं कि वे एक पेशेवर राजनीतिक व्यक्ति बनने की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन उनकी एक बहन रोहिणी आचार्य भी अपने बेलगामी बोल के लिए अक्सर चर्चा का कारण बनती रहती हैं। अब एक बार फिर वे विवादों में फिर गई हैं। इस बार उन पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बिहार के सारण में लोकसभा चुनाव 2024 के 05वें चरण की वोटिंग के दौरान 20 मई की शाम को भिखारी ठाकुर चौक के पास बूथ संख्या 118 पर अपने समर्थकों के साथ पहुंच कर रोहिणी ने मतदाताओं से दुर्व्यवहार किया था। हालांकि आक्रोशित भीड़ को देखते हुए वे खुद तो वहां से निकल गईं, लेकिन जाते-जाते हिंसा की आग भड़का गई। अगले दिन सुबह हुए बवाल में तीन लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग, जब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने घटना को राजद-भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच का झड़प बताया, जबकि सूत्र बताते हैं कि घटना का मुख्य कारण दो जातियों राजपूत और यादव के बीच के विवाद का उन्मादी होना था। देखा जाए तो रोहिणी के राजनीतिक तौर-तरिकों में वही पुराना राजनीति का लालू मॉडल या कहा जाए कि लालू कर राजनीति वाला अंदाज दिखाई पड़ता है, जो बिहार में 1990 से 2005 के बीच लालू यादव के 15 वर्षों के शासन वाले दौर की याद कराता है।

बिहार चुनाव परिणाम की किसी ने अब तक कल्पना नहीं की होगी

नीरज कुमार दुबे

बिहार में भाजपा का प्रयास है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करे इसलिए पार्टी ने नारा दिया है अबकी बार 40 हमारा, मोदी सगे हमारा बिहार। बिहार में इस बार भाजपा ने कुछ सीटों पर सांसदों के टिकट काट कर नये लोगों को मौका दिया है जिसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ और सीटें ऐसी थीं जहां यदि उम्मीदवार को बदला जाता तो स्थिति और अच्छी हो सकती थी। भाजपा के पास पूरा फीडबैक है इसलिए पार्टी आलाकमान असंतोष व्यक्त कर रहे लोगों को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री जिस तरह यहां लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और राज्य में अपने हर दौरे के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ कर वर्तमान चरण की तैयारियों की समीक्षा और आगे के चरण के लिए रोडमैप बना रहे हैं उससे बिहार भाजपा एकदम चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज भी बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावी है।

मौडिया की चुनाव यात्रा जब बिहार पहुँची तो हमने पाया कि यहां के लोग इस बात से बेहद प्रसन्न हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। हमने खासतौर पर पटना, पाटलिपुत्र, आरा, काराकाट और बक्सर संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर जब वहां के हालात जाने तो एक चीज स्पष्ट हुई कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक लोगों को पहुँच रहा है जिसके चलते सभी लोग मोदी के मुरीद बने हुए हैं। हमने जब राम मंदिर को लेकर लोगों से बातचीत की तो सभी ने कहा कि मोदी ने वादा पूरा किया यह अच्छी बात है लेकिन राम मंदिर इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है बल्कि मुद्दा यह है कि मोदी जो कहते हैं वह पूरा करते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री के बारे में और स्थानीय उम्मीदवारों के बारे में जब हमने जनमत को टटोला तो वह सभी सीटों पर थोड़ा अलग नजर आया। यदि काराकाट की बात करें तो यहां से एनडीए के



उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा सिलेंडर चुनाव चिह्न पर मैदान में हैं। वह यहां से पहले भी सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जनता से सीधा जुड़ाव नहीं रखना उनके विरोध में जा रहा है। लोगों को उनका बार-बार पार्टी बदलना और अपनी नई पार्टी बना लेना भी नहीं भा रहा है लेकिन चूँकि काराकाट कुशवाहा बहुल है इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद है कि वह एक बार फिर चुनाव जीत सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके समर्थन में एक रैली को संबोधित कर चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके लिए प्रचार किया। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने यहां से राजाराम कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है जिसके चलते कुशवाहा समाज के मत विभाजित हो सकते हैं।

हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल का यहां अच्छा प्रदर्शन रहा था और उसने इस संसदीय सीट की एक सीट छोड़कर बाकी पर विजय हासिल की थी। यहां चुनाव को त्रिकोणीय बनाते हुए भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह मैदान में हैं। उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए अन्य प्रत्याशियों के होश उड़े हुए हैं। पवन सिंह के साथ युवा खासी तादाद में हैं। इन युवाओं पर उपेन्द्र कुशवाहा ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके चलते युवा वर्ग उनसे और नाराज हो गया है। जब हमने कई गांवों का दौरा कर लोगों से बातचीत की तो अधिकांश

लोगों ने कहा कि हम पवन सिंह का साथ देंगे क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं। लोगों ने कहा कि पहले हमारे पास विकल्प नहीं था इसलिए हम एनडीए या इंडिया गठबंधन में से ही किसी को चुनते थे लेकिन इस बार हमारे पास अच्छा विकल्प है। कई लोगों ने कहा कि वह चूँकि पवन सिंह के फैन हैं इसलिए उनको ही वोट देंगे। इन लोगों ने यह माना कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ यह ले रहे हैं लेकिन वोट पवन सिंह को देंगे। उन्होंने कहा कि हम मोदी के खिलाफ नहीं हैं और यदि चुनाव बाद पवन सिंह मोदी के साथ चले जायें तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस हम तो उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि काराकाट में दो लाख के आसपास राजपूत हैं और पवन सिंह को उम्मीद है कि वह सारा वोट तो उनको मिलेगा ही साथ ही अन्य समाज का भी समर्थन उन्हें मिलेगा।

जब हमने आरा और बक्सर संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया तो पाया कि आरा में आरके सिंह के आगे कोई किसी अन्य प्रत्याशी की बात भी नहीं कर रहा है। लोगों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार आरके सिंह जिस इमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने गांवों में विकास अपने करवाये हैं उससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है इसलिए लोग उन्हीं का साथ देंगे। बहरहाल, यह सही है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है लेकिन इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनावों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस की बात करें तो हाल के चरणों में तो पार्टी का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए ही नहीं आया। यहां प्रचार का सारा भार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने ही उठा रखा है। लेकिन वह गंभीरता के साथ प्रचार करने की बजाय अपने वीडियो को वायरल कराने का प्रयास करते ज्यादा नजर आये। नीतीश कुमार ने भी काफी शिद्द से प्रचार किया जिससे वह विपक्ष के उन आरोपों का जवाब दे सकें जिसके तहत कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है।

शेषन के सुधार और कंपनियों के प्रचार से उतरा चुनावों का खुमार

संजय तिवारी

यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा की बची हुई कुल 57 सीटों पर मतदान के साथ एक जून को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव पूरा हो जाएगा। लगभग 100 करोड़ मतदाताओं वाले लोकतंत्र में चुनाव आया और चला गया लेकिन क्या आपको उस तरह से पता चला जैसे पहले पता चलता था?

जिन लोगों का जन्म चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन के कार्यकाल के बाद हुआ है उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भारत में चुनाव का मतलब असल में क्या होता था। उस समय तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के नीचे थी लेकिन चुनाव की गहमा गहमी इतनी अधिक रहती थी कि शायद ही कोई हो जो इसका हिस्सा बनने से अपने आपको रोक पाये।

उन दिनों न केवल मतदान बैलट पेपर पर होते थे बल्कि पूरा चुनाव प्रचार बैनर और पोस्टरों के सहारे लड़ा जाता था। हर दल भीषण जनसंपर्क करता था और इसके लिए हर लोकसभा सीट या विधानसभा सीट पर सैकड़ों टोलियां बनायी जाती थीं। चौक-चौराहों और चाय पान नाश्ते जलपान की दुकानों पर जहां चले जाइये वहां हफ्तों चुनावी चर्चा चलती रहती थी।

लेकिन 1990 में चुनाव आयुक्त बने टीएन शेषन ने जो %कठोर% चुनाव सुधार किये उसने तात्कालिक रूप से उतना असर तो नहीं पैदा किया लेकिन दीर्घकालिक रूप से चुनावी प्रक्रिया को ही एक सरकारी खानापूति बना दिया। जिस समय टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे निश्चित रूप से वह भारतीय राजनीति का सबसे उथल पुथल भर और अस्थिर काल था। टीएन शेषन न होते तो भारत का लोकतंत्र कहां पहुंच जाता कोई नहीं जानता। लेकिन उनके भीषण चुनाव सुधार ने उस समय तो लगा कि बेलगाम होते नेताओं पर नकेल कसकर लोकतंत्र को बचा लिया लेकिन वहीं से चुनावों के प्रति जनता की गहमा गहमी भी खत्म होने लगी।

टीएन शेषन के चुनाव सुधार ने भारत के चुनाव में फिजूलखर्ची रोकने के लिए चुनावी खर्चों की जो सीमा बांधी थी उसने भारतीय लोकतंत्र की उत्सवधर्मिता को ही मानो खत्म कर दिया। जंगल काटकर घर बनाने और गमले



में पौधा लगाकर पर्यावरण बचानेवालों ने टीएन शेषन के इन चुनावी सुधारों को पर्यावरण से जोड़कर भी देखा कि अब जब पेपर का इस्तेमाल कम होगा तो पेड़ कम कटेंगे, पेड़ कम कटेंगे तो पर्यावरण बचेगा।

शेषन के चुनाव सुधार ने उन बेलगाम गंवई और देहाती लोगों को सुधारने का काम भी किया जो शहरी लोगों की नजर में चुनाव आते ही हुड़दंग मचा देते थे। रही सही कसर 2004 में ईवीएम के इस्तेमाल ने पूरी कर दी। तकनीकी की तरफ आंख मूंदकर दौड़ते भारत के लोगों को यह समझाया गया कि जब टेक्नालाजी इतनी एडवांस हो गयी है कि एक बटन दबाने से काम हो जाता है तो फिर कागज के बैलट पर ठप्पा मोहर मारकर उन्हें डब्बा में भरने की जरूरत क्या है?

टीएन शेषन ने जो चुनाव सुधार किया था उसका असर आने में समय जरूर लगा लेकिन असर हुआ। उसकाल, हर उम्मीदवार को एक निश्चित सीमा तक ही पैसा खर्च करने की अनुमति दी गयी। इससे चुनाव में फिजूलखर्ची पर रोक तो लगी लेकिन इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जो कारोबार पैदा होता था, वह खत्म हो गया। पहले पार्टियां उम्मीदवारों को अपनी ओर से कुछ पैसा देती थीं ताकि उम्मीदवार जमकर चुनाव लड़ सकें। अब क्योंकि उसके खर्च की सीमा निर्धारित हो गयी है तो पार्टियों ने बजाय उम्मीदवार को पैसा देने के, पार्टी के प्रचार पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। इससे चुनाव आयोग की बंदिश भी खत्म हो गयी और पार्टी सिम्बल का प्रचार भी हो गया।

इस तरीके का सबसे अधिक इस्तेमाल भाजपा में मोदी शाह की जोड़ी ने किया है। मोदी शाह के आगमन से पहले 2009 से ही भाजपा ने कॉरपोरेट घरानों को चुनावी व्यापार देना शुरू कर दिया था। चुनावी रणनीतिकार, रिसर्च,

सर्वेक्षण, टीवी-अखबार और डिजिटल मौडिया में प्रचार के साथ साथ आउटडोर और परिवहन माध्यमों से भी प्रचार प्रसार कुछ क्षेत्र विकसित हो गये जिसमें पार्टी वर्कर नहीं बल्कि व्यावसायिक कंपनियों के प्रोफेशनल काम करते हैं। अब चुनाव सामान्य पार्टी समर्थकों के लिए लाभ का अवसर होने के बजाय बड़े व्यावसायिक घरानों के लिए लाभ का अवसर बन गया।

जब भाजपा ने ये तरीके अपनाते शुरू किये तो कांग्रेस ने भी अपने परंपरागत प्रचार तंत्र को शिथिल करते हुए कंपनियों के जरिए प्रचार पर जोर देना शुरू कर दिया। 2014 से कांग्रेस ने भी वो तरीके अपनाने शुरू कर दिये जिसमें भाजपा मौलों आगे निकल चुकी थी। इस तरह चुनाव में फिजूलखर्ची तो रुकी लेकिन केवल स्थानीय स्तर के समर्थकों या प्रचार सामग्री छापने वालों के लिए। चुनावी खर्च कम नहीं हुआ। वह पैसा कॉरपोरेट घरानों की ओर चला गया और चुनाव भी एक प्रकार की ऐसी कॉरपोरेट गतिविधि बनता जा रहा है जहां कुछ कंपनियों के लिए करोड़ों, अरबों का बिजनेस जनरेट होता है।

इसका असर स्थानीय लोगों के उत्साह पर पड़ना था और वह 2024 में भरपूर दिखाई दे रहा है। 2024 का आम चुनाव बीते दो दशक का सबसे उदास और निराश चुनाव लग रहा है। भाजपा की ओर से खर्चों और चुनाव प्रचार का अत्यधिक केन्द्रीयकरण कर दिया गया है। भाजपा का सारा जोर मोदी और कमल निशान के प्रचार पर है। अलग अलग मौडिया माध्यमों से उन्हीं का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। उसकी रणनीति संभवतः यह है कि जब लोगों को बटन कमल के निशान पर ही दबाना है और ऐसा करवाने के लिए उनके पास ब्रांड मोदी है तो किसी और पर पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है?

कुछ ऐसी ही रणनीति दूसरे दलों की भी बनती जा रही है। अपने पार्टी सिम्बल और केन्द्रीय नेता के प्रचार पर हर दल जोर दे रहे हैं और स्थानीय गतिविधियों को सीमित करके अधिक से अधिक कॉरपोरेट शैली में काम करने को बेहतर मान रहे हैं। इसका नतीज यह हो रहा है कि स्थानीय समर्थक अपनी पार्टियों के प्रति इस बार उदासीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह संकट अकेले बीजेपी के साथ है। बाकी दलों में भी कमोबेश यही हाल है जिसके कारण 2024 का आम चुनाव एक खानापूति बनकर रह गया है।

बंगाल में भाजपा का एकतरफा लड़ाई का दावा

अकिंत सिंह

लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिम बंगाल बेहद ही अहम राज्य होता है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं जहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने-सामने है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल से काफी उम्मीदें कर रही है। यही कारण है कि भाजपा के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई को एकतरफा बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं की पार्टी 30 के आसपास सीटों पर जीत हासिल करेगी। आज खुद



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा पश्चिम बंगाल में कितना कमाल कर पाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल चुनाव में टीएमसी पार्टी अपने अस्तित्व को लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में हम 3 थे और बंगाल की जनता ने हमें 80 (सीटों) पर पहुंचाया, पिछले लोकसभा चुनाव में हमें भारी बहुमत मिला। इस बार भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल रहने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव एकतरफा है, लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसके कारण सरकार में बैठे लोग, टीएमसी के लोग हताश हैं। उनहोंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। इन तमाम अत्याचारों के बावजूद ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं और वोटों की संख्या भी बढ़ रही है। मोदी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में नहीं लौटेगी और इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगी। ममता ने कहा, “मोदीजी को चुनाव प्रचार करने का पूरा हक है। उन्हें यहां आने और चुनावी रैलियां करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि उन्हें उनकी पार्टी (भाजपा) के चुनावी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री कहा जा रहा है।” तृणमूल प्रमुख ने भाजपा पर वोट हासिल करने के लिए समुदायों के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया और इसे एक “खतरनाक खेल” करार दिया। उन्होंने कहा, “मैं सभी समुदायों के लोगों से प्रचार करती हूँ। मैं मारवाड़ी, बिहारी और अन्य से प्यार करती हूँ, जो साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का खूबसूरत ताना-बाना बनाते हैं।” ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई तृणमूल कांग्रेस (टीएमपीसी) सरकार को उखाड़ फेंकने की उसकी (भाजपा की) आकांक्षा अधूरी रहेगी। भाजपा ने इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल में राज्य के अस्मिता को लेकर लड़ा है। महिलाओं को साधने की कोशिश की है। संदेशखाली की घटना को जबरदस्त तरीके से सियासी रंग भी देने की कोशिश हुई है। इसके अलावा भाजपा को इस बात का भरोसा है कि राज्य के लोग ममता बनर्जी से अब नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का मानना है कि राज्य में अवैध घुसपैट की वजह से यहां के स्थानीय निवासी में नाराजगी है। इसके अलावा पार्टी की ओर से राज्य में ध्वंसिकरण की भी कोशिश की गई है। पार्टी की ओर से बार-बार कहा गया कि सीएए लागू कर दिया गया है जिसका फायदा बंगाल में रह रहे कई समुदायों को हो सकता है। बंगाल में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत भी लगाई है। 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी का दावा है कि इन आंकड़ों में वृद्धि होगी।

कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में कैरियर के ये हैं मौके



कॉस्ट्यूम डिजाइनर किसी विशेष दृश्य या वस्तुस्थिति के अनुरूप विशेष परिधान डिजाइन करते हैं। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी, वस्तुस्थिति को समझकर उसे साकार करने की क्षमता, परिधान को कम्प्यूटर द्वारा थ्री-डी इफेक्ट में डिजाइन करने की क्षमता, बेहतर कम्यूनिकेशन और लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री, फैशन शो, फैन्सी ड्रेस शो, थिएटर व विभिन्न इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में काम तलाश सकते हैं। आप ड्रेस मैटीरियल से संबंधित इम्पोर्ट हाउसेज, मैयूफैक्ट्रिंग यूनिट्स, फैन्सी रिटेल आउटलेट्स, फैशन जर्नलिज्म एवं एडवटाइजिंग एजेंसी से भी अपने जॉब्स की शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से संबंधित कोई विशेष पाठ्यक्रम भारत में उपलब्ध नहीं है, बल्कि कई संस्थानों में इसे फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही एक विशेष पेपर के रूप में शामिल किया है। अतः देश में उपलब्ध विभिन्न संस्थानों से फैशन डिजाइनिंग से संबंधित डिप्लोमा व डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से संबंधित किसी प्रतिष्ठान के साथ जुड़ कर कार्य-अनुभव व इस क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराने वाले प्रमुख संस्थानों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद शामिल हैं।

एसबीआई ने जारी किया क्लर्क मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड

भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट (ग्राहक सहायता और विक्री) के पद के लिए 09 जून को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट- sbi.co.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन छात्रों की परीक्षा उल्लिखित तिथि पर निर्धारित है, वे मुख्य प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 8773 पदों को भरना है।

- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे पंजीकरण/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि की आवश्यकता होगी।
- भारतीय स्टेट बैंक ने लद्दाख क्षेत्र और उन उम्मीदवारों के लिए एसबीआई क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2024 जारी किया है जिनकी परीक्षा 25 फरवरी और 04 मार्च 2024 को आयोजित नहीं की गई थी।

- कॉल लेटर पर उल्लिखित विवरण**
- उम्मीदवार का नाम
 - उम्मीदवार का रोल नंबर
 - लिंग
 - आवेदक का फोटो
 - उम्मीदवार की जन्मतिथि
 - परीक्षा तिथि, समय और स्थान
 - उम्मीदवार के पिता और माता का नाम
 - परीक्षा केंद्र का पता
 - परीक्षा केंद्र का नाम
 - पोस्ट नाम
 - परीक्षा की अवधि
 - परीक्षा का नाम
 - परीक्षा केंद्र कोड
 - उम्मीदवार के हस्ताक्षर के लिए स्थान
 - पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के लिए स्थान

परीक्षा के दौरान इन दिशानिर्देशों का जरूर पालन करें

- परीक्षा केंद्र परीक्षा समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचने
- उम्मीदवार को अपने एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड 2023 के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे।
- परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न ले जाएं।
- एसबीआई क्लर्क स्थल किसी भी प्रकार की किताबें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रतियां, आभूषण, बेल्ट आदि की अनुमति नहीं देगा।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

- एसबीआई के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण नीचे दिए गए हैं।
- सबसे पहले उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब जिसमें ये लिखा है मुख्य परीक्षा कॉल लेटर डाउनलोड करें (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिनकी परीक्षा फरवरी/मार्च 2024 में आयोजित नहीं हुई थी) पर क्लिक करें
- अब, आपको अपने एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे पंजीकरण नंबर, पासवर्ड और रोल नंबर जमा करना होगा।
- केप्चा बॉक्स भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड 2023-24 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसकी एक प्रति अपने पास जरूर रख लें।



स्पा थेरेपिस्ट बन संवारे कैरियर

इस कोर्स में शुरुआत करने वाले स्टूडेंट्स को स्पा थेरेपी की सभी बुनियादी मसाज के तरीके सिखाए जाते हैं और उन्हें एक पेशेवर स्पा थेरेपिस्ट के तौर पर विकसित किया जाता है। इसके तहत इंसानी शरीर की संरचना, शारीरिक क्रिया, आयुर्वेदिक और ओरिएंटल थेरेपियां और एस्थेटिक ट्रीटमेंट जैसे विषयों को शामिल किया गया है।



जब आप किसी स्पा थेरेपिस्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सुखदायक आवाज, कोमल स्पर्श और आराम पहुंचाने वाले बर्ताव की तस्वीर उभरती है। ओरिएंटल स्पा एकेडमी, जिसके कैंपस जयपुर और अहमदाबाद में हैं, स्पा थेरेपी में प्रोफेशनल डिप्लोमा का कोर्स कराती है। यह कोर्स कोई भी कर सकता है, बशर्ते उसे लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से आराम पहुंचाने में रुचि हो और वह उसमें अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखता हो। इस कोर्स में शुरुआत करने वाले स्टूडेंट्स को स्पा थेरेपी की सभी बुनियादी मसाज के तरीके सिखाए जाते हैं और उन्हें एक पेशेवर स्पा थेरेपिस्ट के तौर पर विकसित किया जाता है।

इसके तहत इंसानी शरीर की संरचना, शारीरिक क्रिया, आयुर्वेदिक और ओरिएंटल थेरेपियां और एस्थेटिक ट्रीटमेंट जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इसमें कल्चर और कम्यूनिकेशन पर भी मॉड्यूल रखा गया है, जो बहुत जरूरी है ताकि स्टूडेंट यह सीख सकें कि स्पा में कैसा माहौल होना चाहिए और एक स्पा थेरेपिस्ट के तौर पर उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस कोर्स के एक अनिवार्य अंग के रूप में छात्रों को किसी पांचतारा स्पा रिसॉर्ट में प्रोफेशनल अनुभव लेने के लिए कहा जाता है। यह संस्थान स्पा मैनेजमेंट और ऑपरेशंस पर भी प्रोग्राम चलाता है।

नौकरी के मौके: इस कोर्स को पूरा करने वाले स्टूडेंट किसी स्पा और रिसॉर्ट में थेरेपिस्ट या एस्थेटिशियन की नौकरी पा सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप स्वतंत्र रूप से अपना स्पा भी स्थापित कर सकते हैं।
सैलरी: पहले साल में शुरुआती वेतन एक से दो लाख रु. तक हो सकता है।

ऐसे बनाएं साख मजबूत



आज के समय में प्रोफेशनल्स और संस्थाएं अपनी साख के लिए काफी हद तक मीडिया पर निर्भर हैं। आपसे जुड़ी किसी तरह की बुरी खबर, तस्वीर, समाचार, समीक्षा आदि चाहे वे सरासर झूठ ही क्यों न हों, उन्हें आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। इसीलिए अपनी साख का प्रबंधन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

साख का प्रबंधन क्यों हो पहली वरीयता

- कैसे निगरानी रखेंगे आप?
- हर खबर से वाकिफ रहने के लिए पेशे से जुड़े नेटवर्क, अखबारों, कंपनी से जुड़ी फोरम की गतिविधियों पर ध्यान दें।
- अपनी कंपनी और सेवाओं के बारे में लोगों तक पहुंच रही जानकारी पर नजर रखें।
- अपने लक्ष्यों को समझें।
- प्रचार-प्रसार के कामों पर रखें नजर।
- उपभोक्ता से मिल रहे फीडबैक को गंभीरता से लें
- अपने उद्योग को प्रभावित करने वाले लोगों को पहचानें।
- आपकी प्रतिष्ठा बनाने या बिगाड़ने का दारोमदार उपभोक्ता, साझेदार, निवेशक, कर्मचारी, पत्रकार और प्रतिद्वंद्वियों पर होगा।
- सोशल मीडिया पर बढ़ाएँ संपर्कों का दायरा।
- साख पर हमला करने वालों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाएं।
- नाखुश कर्मचारियों की करें पहचान।

आपके प्रतिद्वंद्वी किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस पर नजर रखें।

ऑनलाइन निगरानी

मुफ्त ऑनलाइन टूल्स में निगरानी रखने के लिए गूगल एलर्ट और सोशल मेंशन जैसे टूल्स का सहारा लिया जा सकता है। शुल्क लेकर निगरानी करने वाले टूल्स जैसे कि ट्रेकर व्यापक स्तर पर निगरानी और विस्तार में रिपोर्ट देते हैं और सूचनाओं से होने वाले असर के बारे में भी बताते हैं।

बातचीत की निगरानी कौन करेगा?

कंपनी से जुड़े इंटरनेट आसानी से घुल-मिल जाते हैं, लेकिन मुमकिन है कि वे कंपनी के मूल्यों को लेकर संजीदा न हों और न ही कंपनी के लक्ष्यों को समझ पाएं।

पीआर संस्थाएं

ये संस्थाएं प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं, लेकिन मुमकिन है कि काम के बोझ के कारण वे उपभोक्ताओं का नजरिया न समझ सकें।

कंपनी के बड़े पदाधिकारी

ये अफसर उपभोक्ताओं की बात का मूल्य समझ सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया मिलने में देरी भी हो सकती है।

कंपनी मैनेजर

यह ग्राहक को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं और आपकी साख की निगरानी का काम भी बखूबी करते हैं।

ये बोरियत दूर क्यों नहीं होती!

बोरियत बुरी चीज नहीं है। गलत उसे लंबे समय तक पकड़े रहना है। मन कहीं टिकता ही नहीं हमारा। ऐसा तो नहीं, उंगलियों की तरह दिल और दिमाग भी टच स्क्रीन के आदी हो गए हैं? हर समय कुछ नया स्करोल करने की बेचैनी खुश नहीं रहने देती। ऊब रहे हैं। पर पता नहीं क्यों? बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक जैसा काम, वही लोग और एक सी बातें। जीवन में कुछ रोमांच ही नहीं। उबाऊपने का यह एहसास दिनभर में कई बार कचोटता है। जितनी लंबी हमारी बोरियत होती है, उदासी भी बढ़ती चली जाती है। कई बार उकताकर कह उठते हैं कि बाकी सही है, शायद हम ही बोर हैं! वजह जो भी हो, बोरियत कई तरह से हम पर असर डालती है।

क्यों होती है बोरियत?

आसान शब्दों में कहें तो बोरियत, काम और हालात से हमारे जुड़ाव की कमी है, जिसके कारण काम में मन नहीं लगता। यॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन ईस्टवुड ने बोरियत पर काफी काम किया है। वे इसे दो तरह के व्यक्तित्वों से जोड़ते हैं। उनके अनुसार, 'कुछ लोगों में यह महज कुछ नया ना कर पाने की बेचैनी होती है। ऐसे लोग हर समय कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं। दूसरी स्थिति में यह हमारे भीतर के डर की उपज होती है, जिससे बचने के लिए लोग खुद को सुरक्षित घेरे में कैद कर लेते हैं।' विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों को बहुत अधिक रोका-टोका जाता है, उनका भी किसी काम में मन नहीं लगता। सूजी कासेम तो यहां

तक कहती हैं, 'दूसरों की चुगली या बुराई करने वाले लोग बोरियत और कड़वाहट को हर दम साथ लेकर चलते हैं।' पर असली समस्या तब होती है, जब बोरियत दूर करने के लिए हम शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका में हुए एक शोध में किशोरों में शराब, सिगरेट और नशीली दवाओं की लत का एक बड़ा कारण गहन बोरियत पायी गयी है। यह हमारी काम करने की इच्छा को ही कम कर देती है।

थोड़ा ऊबना जरूरी है

टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विषय की प्रोफेसर होवर लेंच कहती हैं, 'बोरियत हमें एक ही ढर्रे पर चलने से रोकती है। नए लक्ष्य और नए अनुभव हासिल करने की प्रेरणा देती है।' इस मायने में हमारी बोरियत हमें कुछ नया रचने और नया सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। दार्शनिक आर्थर शॉपेनावर कहते हैं, 'जीवन की व्यर्थता का एहसास बोरियत से भर देता है, तो इसकी सार्थकता समझने वालों को बोर होने का समय ही नहीं मिलता।' अपनी बोरियत से भागे नहीं। उसे समझें। इस विशाल

धरती पर हमारा समय बेहद सीमित है। क्या वाकई हमारे पास बोर होने की फुर्सत है? **● पूनम जैन**



स्मार्ट-स्टाइलिश स्लाउची बैग्स



स्लाउची बैग्स से अर्थ है सॉफ्ट मैटीरियल से बने ऐसे बैग्स, जिन्हें मोड़कर रखने के बाद भी वह अपने पहले से शोप में आ जाएं।



स्मार्ट लुक को कंप्लीट करने में स्टाइलिश एक्सेसरीज की रहती है अहम भूमिका। फैशन पर नजर डालें तो इस लिहाज से स्लिफ बैग्स का जमाना गया, अब तो सॉफ्ट स्लाउची बैग्स हैं इन। स्लाउची बैग्स से अर्थ है सॉफ्ट मैटीरियल से बने ऐसे बैग्स, जिन्हें मोड़कर रखने के बाद भी वह अपने पहले से शोप में आ जाएं। फैशन विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैक या ब्राउन के बजाय ब्राइट रेनबो कलर्स यानी पिंक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल इत्यादि में ओवरसाइज स्लाउची बैग्स इन दिनों युवतियों के बीच अधिक पसंद किए जा रहे हैं। रंगों में छिपी होती है मस्ती, ऐसे में जब आप कैरी करेंगी

कलरफुल स्लाउची बैग तो आपकी पर्सनॉलिटी में जुड़ जाएगी कलरफुल अदा। ब्राइट कलर्स में शाइनी ओवरसाइज स्लाउची बैग की खासियत है कि एक ओर जहां इनमें आप अपनी जरूरत का हर सामान कैरी कर सकती हैं, वहीं ये बनते हैं आपका स्टाइल स्टेटमेंट।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

राहुल-अखिलेश अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे: शाह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, पांच चरण के मतदान में ही मोदी 310 पार कर गए हैं। छठे और सातवें चरण का मतदान 400 पार कराने का है। राहुल बाबा 40 सीट भी पार नहीं कर रहे हैं और अखिलेश जी 4 के अंदर रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून को काउंटिंग है, 4 जून की दोपहर को ये दोनों शहजादे (राहुल गांधी और अखिलेश यादव) प्रेस कांफ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम खराब थी, इसलिए हम हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि राहुल बाबा हमें डराते हैं कि पीओके मत मांगो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, हम एटम बम से नहीं डरते हैं। पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने संविधान का मजाक उड़ाया है। बीआर अंबेडकर की भावनाओं के खिलाफ जाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जबरन संविधान में धारा 370 डाल दी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के जरिए संविधान का गला चोटने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने लगातार कोशिश की कि एससी/एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंध लगाकर इसका कुछ लाभ अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 के चुनाव में अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह मुसलमानों को भी आरक्षण देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के फैसले को पूरी तरह से हलट दिया है और कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण : आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने संविधान का मजाक उड़ाया है। बीआर अंबेडकर की भावनाओं के खिलाफ जाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जबरन संविधान में धारा 370 डाल दी। उन्होंने कहा कि आपातकाल के जरिए संविधान का गला चोटने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने लगातार कोशिश की कि एससी/एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंध लगाकर इसका कुछ लाभ अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 के चुनाव में अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह मुसलमानों को भी आरक्षण देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के फैसले को पूरी तरह से हलट दिया है और कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

बिहार में कोई सरकार नहीं, केवल नौकरशाही है : तेजस्वी

पटना। बिहार में अलग-अलग जगहों के स्कूलों में कई छात्रों के बेहोश होने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कोई सरकार और लोकतंत्र नहीं है, बल्कि केवल नौकरशाही है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम इतने कमजोर हैं कि स्कूल के समय को लेकर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि तापमान 47 डिग्री है, लू चल रही है और कम से कम छोटे बच्चों को तो थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। राजद नेता ने दावा किया कि बिहार में स्कूलों का बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं है... लेकिन, सीएम के हाथ में कुछ नहीं है। दरअसल, उमस भरी भीषण गर्मी में स्कूल खोलने का फरमान गलत साबित हो रहा है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को कोई चिंता नहीं हुई है। कई स्कूलों में बच्चों की तबियत खराब हो जा रही है।

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर कि उन्हें परमात्मा ने एक उद्देश्य के लिए भेजा है पर तंज कसते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देवताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए और दंगे नहीं भड़काने चाहिए। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि अगर मोदी खुद को भगवान मानते हैं तो उनके लिए एक मंदिर बनाया जाना चाहिए ताकि वह वहां बैठें और देश को परेशान करना बंद कर दें। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मजाकिया लहजे में कहा कि एक कहता है कि वह (पीएम मोदी) देवताओं के भगवान हैं। एक नेता कहते हैं भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं। अगर वह भगवान हैं, तो भगवान को राजनीति नहीं करनी चाहिए। भगवान दंगे न भड़काएं। हम उनके लिए एक मंदिर बनाएंगे और वहां उनकी पूजा करेंगे, प्रसाद, फूल चढ़ाएंगे और अगर वह चाहें तो हम उन्हें ढोकला भी चढ़ाएंगे।

केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने के लिए सात दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गयी है तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति जे के माधेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सोबीज) फैसला ले सकते हैं क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।

बंगाल में प्रधानमंत्री ने भरी हुंकार, राज्य सरकार पर लगाए आरोप

टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म कर देगी : मोदी

कोलकाता। सातवें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी। उन्होंने मथुरापुर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने रैली में राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और इंडी गठबंधन की जमकर आलोचना की। टीएमसी पर उन्होंने केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक नहीं पहुंचाने, बंगाल की संस्कृति की रक्षा न करने और राज्य की पहचान खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि चार जून को देश में एक बड़ा मोड़ आएगा, जिसमें वे और उनकी सरकार अगले पांच साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं।



देश की जनता लड़ रही है। क्योंकि, उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है।

पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन (चार जून) को देश का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट बताया। उन्होंने कहा, आने वाले पांच साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट है। और इसकी शुरुआत चार जून को होने जा रही है। विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ऐसे सांसद चुने, जो इस विजन को लेकर चलें। इसलिए मुझे बंगाल से ज्यादा से ज्यादा आप कमल जीताकर भेजेंगे, इसका आशीर्वाद चाहिए। भाजपा पर बंगाल के लोगों का प्यार तृणमूल को बदल नहीं हो रहा है इसलिए तृणमूल पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्या-क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी तृणमूल के पास एक ही हथियार बचा है, 'हम ऐसा नहीं होने देंगे'। विकास के जो काम मोदी करता है, तृणमूल कहती है कि 'ऐटा होते देबो ना' यानि कि 'हम ऐसा नहीं होने देंगे'।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब तो तृणमूल सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों-पिछड़ों को आरक्षण दिया है लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी प्रमाणपत्र बनाए जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार हैं। 1 जून को आपका एक वोट इन खरबनाक इरादों को रोकेगा। उन्होंने आगे कहा, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मामलों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव खुद आगे बढ़कर

क्या ऐसी तृणमूल को आप सजा देंगे? उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मतों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रहे। टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। ऐसी टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तृणमूल ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं कि समानदारी से विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। आप भाजपा को बंगाल में मजबूत कीजिए, आपकी हर अपेक्षा भाजपा ही पूरा करेगी।

लूट का माल कहीं भी छिपा लें, मोदी पाई-पाई निकालेंगे

ओडिशा के मयूरभंज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूँ, मुझे अपार प्यार और उत्साह मिलता है। लोगों का मुझे पूर्ण विश्वास इस बात का प्रमाण है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है। देश को सचमुच मजबूत मोदी सरकार मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो विकास भारत के लोगों ने कई दशकों में नहीं देखा वह एक दशक में ही दिखाई देने लगा। मोदी ने कहा कि 2014 में हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। विपक्ष पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि बीजेडी पर आपने 25 साल भरसा किया, लेकिन बीजेडी ने हर कदम पर आपके भरसो को तोड़ा है। यही बीजेडी सरकार आदिवासी बंधुओं की जमीन हड़पने के लिए कानून लेकर आई थी। भाजपा के दबाव में उसे वो कानून वापस लेना पड़ा। अब इस बार अगर इन्हें मौका मिला, तो ये आदिवासियों की जमीन हड़पने का अवसर छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेडी ने आपकी खनिज संपदा को भी लूटा है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाकर हजारों करोड़ रुपये ओडिशा को दिए। बीजेडी में इसमें भी घोटाला कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ओडिशा का लूटा हुआ पैसा विदेशों तक जा रहा है। लूट का माल ये कहीं भी छिपा लें, मोदी पाई-पाई निकालेंगे।

लुधियाना में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना, कहा-

मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया : राहुल गांधी

चंडीगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी। कांग्रेस नेता ने पंजाब में नशीली दवाओं की समस्या का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस खतरे को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। दाखा में लुधियाना से कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने के लिए है। उन्होंने अपनी पार्टी के चुनावी वादों के बारे में भी बात की, जिसमें महालक्ष्मी योजना, किसानों के लिए ऋण माफी और इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना शामिल है।



पसीना लगाता है, लेकिन मोदी ने दस साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया।

गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार, किसी पार्टी और उनके नेताओं ने कहा है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो वे संविधान बदल देंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेते हुए कहा कि यह कोई किताब नहीं बल्कि गरीबों की आवाज है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है क्योंकि उन्होंने भाजपा पार्टी पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं देने का आरोप लगाया।

उन्होंने आगे किसान-अनुकूल फसल बीमा योजना लाने का वादा किया, आरोप लगाया कि वर्तमान बीमा योजना केवल 16 बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाती है। अग्नियुद्ध योजना के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो वह इसे खत्म कर कूड़ेदान में फेंक देगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने पैसा अरबपतियों की जेब में डाला, इन्होंने यह पैसा लंदन, दुबई और विदेशों में खर्च किया। राहुल गांधी ने कहा कि किसान पंजाब व देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसान देश को 24 घंटे भोजन देने में अपना खून

4 जून को परिणाम आने के बाद टूट जाएगा कांग्रेस-आप का गठबंधन?

पंजाब में लोकसभा चुनाव से तीन दिन पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन स्थायी नहीं है। केजरीवाल ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि हमने कोई शादी थोड़ी की है। हमारी कोई मैरिज नहीं हुई है। अरविंद मैरिज नहीं हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल, उनका लक्ष्य सत्तारूढ़ भाजपा को हराना है और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों पार्टियों की स्थानीय इकाइयों ने राज्य में किसी भी संभावित गठबंधन का कड़ा विरोध किया था। पिछले 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में कांग्रेस ने पंजाब में आठ लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि दो-दो सीटें भाजपा और अकाली दल को मिलीं।

खेल प्रमुख समाचार

भारत 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा अभ्यास मैच

न्यूयार्क। टी20 वर्ल्ड कप 2024 को शुरू होने में अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे तो मैच 1 मई से ही शुरू हो रहा है। परंतु वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने की वजह से मुकाबला भारतीय समयानुसार 2 मई से शुरू होगा। इनमें से कुछ मैचों की मेजबानी न्यूयार्क में भी होगी है। इस स्टेडियम में 8 टी20 वर्ल्ड कप मैचों का आयोजन होगा है। होने वाले मुकाबले को लेकर भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच राहुल द्रविड सहित भारतीय क्रिकेटर्स का पहला जत्था कुछ दिन पहले न्यूयार्क पहुंचा था। उप-कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अपनी टीम को बुधवार को जाँइन किया है। मुकाबले को लेकर सभी खिलाड़ी नेट्स पर खूब पसीना भी बहा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की, जिनमें से एक में क्रिकेटर जाँगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी में बुमराह ट्रेनिंग ग्राउंड पर हैं।

मेन इन ब्लू को ग्रुप ए में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, सह-मेजबान यूएसए, आयरलैंड और कनाडा के साथ रखा गया है। वे 5 जून को न्यूयार्क में आयरलैंड के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान की शुरुआत करने से पहले भारतीय टीम को 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेलेगा है। साल 2022 में खेले गए टी20 विश्व कप में भारतीय टीम को सेमाइफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरे नंबर पर जीता था। भारत की एकमात्र टी20 विश्व कप जीत 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में हुई थी, जब उन्होंने दुर्नामेंट के उद्घाटन संस्करण के दौरान दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। मौजूदा टीम को इन सफलता को दोहराने और एक बार फिर ट्रॉफी घर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

आर्थिक/वणिज्य/वित्त प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 667 अंक लुढ़का निफ्टी 22,705 पर बंद

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव करीब-करीब खत्म होने को है और 4 जून को नतीजे आने हैं। इससे पहले शेयर बाजार में निवेशकों के बीच भारी हलचल मची हुई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एक तरफ जहाँ जमकर निकासी कर रहे हैं तो वहीं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी मजबूती आने लगी है। ऐसे में 29 मई को बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। दो दिन पहले ही इंट्रा डे ट्रेड में ऑल टाइम हाई दर्ज करने वाला सेंसेक्स आज 667.55 अंक लुढ़ककर 74,502.90 के लेवल पर बंद हुआ। एमएंडपी बीएसई सेंसेक्स में लिस्टेड 30 शेयरों में से 24 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बता दें कि सेंसेक्स आज 74,826.94 पर ओपन हुआ था। इसी तरह निफ्टी का भी हाल रहा। निफ्टी-50 आज 183.45 अंकों की गिरावट के साथ 22,704.70 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी 28 मई को यह 22,888.15 के लेवल पर बंद हुआ था।

अमेश चतुर्वेदी

इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय भारतीय चुनाव अभियान के दौरान विपक्षी दल महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ साल 2024 में भारत में मुद्रास्फीति साढ़े चार फीसद रहने का अनुमान जता रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में जताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अनुमान रिपोर्ट में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारत के लिए निश्चित तौर पर यह अनुमान सुखद और उत्साहित करने वाला है। इसकी वजह यह है कि दुनिया की विकसित चीजें जाने वाली जिनियादातर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में लगातार गिरावट जारी है।

एमजी मोटर ने एचपीसीएल के साथ किया करार

नई दिल्ली। एमजी मोटर इंडिया ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ साझेदारी की है। एमजी मोटर इंडिया ने बुधवार को बयान में कहा कि इस समझौते के तहत वह एचपीसीएलके साथ मिलकर देशभर के प्रमुख राजमार्गों और शहरों में 50केडब्ल्यू/60केडब्ल्यू डीसी फास्ट चार्जर लगाएगी। वाहन कंपनी ने कहा कि यह साझेदारी ईवी यूजर्स को लंबी दूरी और अंतर-शहर आवागमन के दौरान ईवी चार्जर की उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित है। एमजी मोटर इंडिया के मुख्य वृद्धि अधिकारी गौरव गुप्ता ने कहा, 'भारत में एचपीसीएल का विशाल नेटवर्क और महत्वपूर्ण उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि देशभर में मौजूदा और संभावित ईवी यूजर्स को हमारे चार्जिंग समाधान तक सुविधाजनक पहुंच प्राप्त हो।' उपभोक्ता बाजार तेजी से बढ़ता है। उसमें खपत के लिए निर्माण और उत्पाद का दायरा बढ़ता है। यह पूरी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है और इस तरह जीडीपी में बढ़ोत्तरी होती है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। इसकी वजह से भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार तैयार है। इस बाजार में खपत के लिए तमाम तरह के उत्पादों की जरूरत बढ़ी है इसलिए भारतीय जीडीपी में तेजी आ रही है।

आर्थिक मोर्चे पर भारत का सुनहरा भविष्य

पश्चिमी मुल्कों की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर कमजोर होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन वह अब गिरने लगी है। विश्व बैंक ने मौजूदा साल में उसकी अर्थव्यवस्था में महज साढ़े चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया था, हालांकि अब उसमें उसने थोड़ा सुधार करके उसे 5.2 प्रतिशत की बढ़त का अनुमान लगाया गया है। आखिर भारत में यह बदलाव क्यों हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह अग्रसर क्यों है? इसकी मोटी वजह यहाँ तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचे में भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत में निर्माण गतिविधियाँ भी तेज हैं। यह भी सच है कि भारत के लिए यहाँ की बेतहाशा बढ़ी जनसंख्या भी चुनौती बन रही है। लेकिन इसके साथ ही कटु सत्य यह है कि बढ़ती जनसंख्या के चलते



बाजार लाख बढ़ा हो, अगर सरकारी नीतियाँ उपभोक्ता, उत्पादक, खरीददार और विक्रेता के बीच संतुलन के साथ ही नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाली नहीं होती तो आर्थिक गतिविधियाँ तेज नहीं होती। इस संदर्भ में अंतर है कि भारत में साल 2014 की 350 की तुलना में इन दिनों एक लाख तीस हजार स्टार्ट अप हैं। जिनमें युनिकॉर्न यानी एक अरब की पूंजी वाले स्टार्टअप की संख्या सौ से ज्यादा है। इसके साथ ही सात में पहली बार जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से वसूली 2 लाख करोड़ रुपये के पार हो गई है। मौजूदा साल के अप्रैल में कुल जीएसटी वसूली 2.1 लाख करोड़ रुपये रही, जो साल

2023 के अप्रैल के मुकाबले 12.4 फीसद ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान घरेलू लेन-देन का रहा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 13.4 फीसद बढ़ गया। पिछले साल अप्रैल में सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली हुई थी। वित्त मंत्रालय के एक मई को बताया कि रिफंड के बाद अप्रैल महीने की शुद्ध जीएसटी वसूली 1.92 लाख करोड़ रुपये रही है। जो इसी पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.1 प्रतिशत ज्यादा है। जीएसटी लागू होने के फौरन बाद 2017-18 में जहाँ औसत जीएसटी एक लाख करोड़ रुपये से कम रही, वहीं, कोरोनाकाल के बाद 2020-21 से यह लगातार बढ़ रही है। साल 2022-23 में जीएसटी वसूली औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपये हर महीने रही है। यह बढ़ोत्तरी ही बताने के लिए काफी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर बढ़ रही है।

वित्त मंत्रालय के एक मई को बताया कि रिफंड के बाद अप्रैल महीने की शुद्ध जीएसटी वसूली 1.92 लाख करोड़ रुपये रही है। जो इसी पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.1 प्रतिशत ज्यादा है। जीएसटी लागू होने के फौरन बाद 2017-18 में जहाँ औसत जीएसटी एक लाख करोड़ रुपये से कम रही, वहीं, कोरोनाकाल के बाद 2020-21 से यह लगातार बढ़ रही है। साल 2022-23 में जीएसटी वसूली औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपये हर महीने रही है। यह बढ़ोत्तरी ही बताने के लिए काफी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ सहित झारखंड की सभी लोकसभा सीट जीत रही भाजपा: साय

रायपुर/साहिबगंज/पाकुड़/दुमका। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने साहिबगंज जिले के बरहेट, पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा और दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में सभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 7 मई को लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और हम प्रदेश की सभी ग्यारह को ग्यारह सीटों जीतकर मोदी जी को दे रहे हैं। उन्होंने झारखंड की जनता से प्रदेश की सभी चौदह सीटें भाजपा को जिताकर पीएम मोदी को देने का आग्रह किया।

सीएम साय ने कहा कि झारखंड के लोगों को जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने खूब भ्रमयाया। हमेशा यही भ्रम फैलाते हैं कि मोदी जी और भाजपा सरकार आई तो यहाँ के जल, जंगल, जमीन को लूट लेगी। जबकि पूरे झारखंडवासियों को पता है कि यहाँ के जमीन को लूटने वाला एक मात्र आदमी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जमीन लूटने के मामले में, माइंस के लिए जमीन लेने के मामले में जेल में हैं।

गठबंधन सरकार को घेरते हुए विष्णु देव साय ने कहा कि यहाँ की सरकार में मंत्री, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के पीए के घर से करोड़ों रूपए निकलता है। कांग्रेस के एक सांसद धीरज कुमार के यहाँ छापा पड़ता है तो उसके यहाँ से तीन सौ इन्कवाय करोड़ रूपए घर से निकलता है। ये सारा जनता का पैसा है।



जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन चोर-चोर मौसेरे भाई

झारखंड का दुर्भाग्य कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जमीन लूटने के मामले में जेल में

साय ने झारखंड में ली 3 जनसभाएं, भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट

ये पैसा विकास में नहीं लग रहा है, ये पैसा सड़क, बिजली, पानी के लिए नहीं लग रहा है बल्कि उन्होंने अपने एगो-आराम के लिए रखा है, जो उनके घर से मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम को चोर-चोर मौसेरे भाई बताते हुए जनता से उसे उखाड़ फेंकने की बात कही।

आदिवासियों की विरोधी जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन- मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ने आदिवासियों का कोई विकास नहीं किया। उसे केवल बंधुआ मजदूर समझा, चोट बैंक समझा। भाजपा ने

आदिवासियों का भरपूर सम्मान किया, कर रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने आदिवासियों के हित के लिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बनाया, जहाँ आदिवासी मंत्री पदभार संभालते हैं और बजट की भी कोई कमी नहीं होती है। श्री साय ने कहा कि आज संथाल की एक आदिवासी परिवार की बेटी, बहन द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दायित्व नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सौंपा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का

हित भाजपा में ही सम्भव है। मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का चुनाव- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम साय ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का चुनाव है। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबों की पीड़ा उन्हें पता है। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। गरीबों को गैस सिलेंडर देने, घर बनाने, स्वच्छ पानी, उपचार की सुविधा, खता खुलवाने से लेकर स्वच्छता शौचालय बनवाने

ननिहाल पहुंचे साय

विष्णु देव साय ने सभा की शुरुआत में कहा कि आज वे अपने ननिहाल प्रदेश में आए हैं। झारखंड उनका ननिहाल है। झारखंड से छत्तीसगढ़ का रोटी-बेटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि 'खूंदी लोकसभा क्षेत्र के कुरेड प्रखंड से उनकी माता जी आई हैं और वही उनका मामा गांव है। उनकी दादी भी झारखंड की थीं। उनके सभी मामा भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जुड़वा भाई हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीन राज्य बनाए थे। एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना और पंद्रह नवंबर 2000 को झारखंड बना। दोनों राज्य एक साथ पैदा हुए हैं।

का काम मोदीजी की सोच से संभव हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के साथ देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का काम पिछले दस साल में हुआ है।

डबल इंजन सरकार - खुशियां अपार- मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को गति दे रही है। डबल इंजन की सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मात्र 4 महीने में उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े-बड़े वादे पूरे किये हैं। शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया, 21 फिटल प्रति एकड़ धान खरीद कर 3100

रूपए फिटल धान की कीमत दी और अंतर की राशि 13,320 करोड़ रूपए 24.72 लाख किसानों को देने का काम किया। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने के पहले सप्ताह में 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खातों में एक-एक हजार रूपए की सहायता राशि देने, रामभक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सरकारी खर्च में अयोध्या भेजने और 5500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी की शुरुआत होने की भी बात कही।

भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए की वोट अपील- सीएम साय ने आज यहाँ तीन जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी को हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड की सभी 14 सीटें उनकी झोली में डालनी है। इसके लिए यहाँ की जनता का भरपूर सहयोग मिले, आप सभी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों को जिताएं, ये आग्रह करने आया हूँ।

मंत्री कश्यप का बैज को चुनौती, कहां

हिम्मत है तो मेरे साथ चले नारायणपुर और पखांजूर

रायपुर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। वनमंत्री केशव कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो कांग्रेसी कहें कि किसी एक सीट पर वे जीतेंगे। कांग्रेस नेताओं के ताते उड़ चुके हैं। कांग्रेस मरणसात्र हो चुकी है। अभी वे प्रत्याशी ढूँढ रहे, उसके बाद कार्यकर्ता ढूँढ़ेंगे। फिर वोट ढूँढ़ना होगा, तब तक चुनाव निकल जाएगा। इतना ही नहीं मंत्री केशव कश्यप ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को चुनौती देते हुए कहा कि दीपक बैज मेरे साथ नारायणपुर और पखांजूर चले। मृतक परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात करें। दोनों घटना कांग्रेस पदाधिकारी के माध्यम से हुई। दीपक बैज पुलिस जवानों को बदनाम कर रहे हैं।

वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्री केशव कश्यप ने कहा कि भाजपा 365 दिन कार्य करती है। यह लोकतांत्रिक पार्टी है। एक व्यक्ति के कहने पर वाली पार्टी नहीं है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को चुनौती दे सकता है। हमारी तैयारी पूरी है। लोकसभा का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के लोग किन्तनी तैयारी में है, नजर आ ही रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के अकेले दौरे और बाकी नेताओं की निष्क्रियता को लेकर मंत्री केशव कश्यप ने तंज करते हुए कहा कि दीपक बैज पीसीसी के अध्यक्ष हैं इसलिए जा रहे हैं। लोकसभा के बाद वह भी मिस्टर गायब हो जाएंगे। उनको भी ढूँढ़ना पड़ेगा।

भाजपा के चुनावी अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया के साथियों का अहम रोल: मुख्यमंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश भाजपा की सोशल मीडिया टीम से कल भेंट-मुलाकात एवं अनौपचारिक चर्चा की। श्री साय ने टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के कारगुजारियों एवं भ्रष्टाचार को उजागर किया उससे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में बेहद मदद मिली और अब यही टीम भाजपा सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचा रही है।

सीएम साय ने कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मोदी जी के पिछले 10 साल की उपलब्धियों एवं मोदी की गारंटी के तहत 100 दिन में पूरा किए गए वादों को एवं पिछली कांग्रेस

सरकार की विफलताओं को भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया। उन्होंने कहा



कि आगे आने वाले पांच साल में छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेकर जाना है। मोदी जी के संकल्प पत्र की योजनाओं को लागू करना है और केंद्र एवं राज्य की योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है, जिसमें आप लोगों का रोल अहम होगा। उन्होंने सदस्यों से बीच-बीच में मिलते रहने, आपस में

संवाद करते रहने की बात कही। श्री साय ने कहा कि चुनाव के दौरान इस भीषण गर्मी में केंद्रीय

चुनावी जनसभाएं की। इस पूरे चुनाव प्रचार को आप लोगों ने बखूबी जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का रहा जिसका ये परिणाम है कि हम छत्तीसगढ़ की सभी ग्यारह सीटें जीतने जा रहे हैं।

नक्सलवाद पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसे विपक्ष फेंक बता रहा है। उनके ऐसे सभी झूठी बातों को सकारात्मक एवं वास्तविकता से रेश करना है। इसकी जिम्मेदारी आप सभी सोशल मीडिया के साथियों की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज निचले स्तर तक एवं गांव-गांव तक पहुंचा है, जिसके कारण आप लोगों का योगदान बहुत अहम हो जाता है।

पंजीयन विभाग पर अब होगी विजिलेंस की नजर

अधिकारियों-कर्मचारियों की गड़बड़ी के साथ बड़े पंजीयनों की करेगी निगरानी

रायपुर। पंजीयन विभाग पर अब विजिलेंस सेल की नजर होगी। यह सेल एक करोड़ या 5 करोड़ के पंजीयन की निगरानी करेगा। यह केवल आने वाले दिनों में बड़े पंजीयनों को देखने का काम करेगा। इसे भी पढ़ें - स्वास्थ्य

करोड़ को देखने का काम करेगी। यही नहीं पिछले समय भी जो बड़ी रजिस्ट्री हुई है, उसकी निगरानी करेंगे। आगे जो होंगे, उसके निगरानी करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीयन के मामले में कोई बड़ी गड़बड़ी न हो। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नौकरियों को लेकर कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा की सरकार में ज्यादा भर्तियां होंगी।

सभी विभाग अपने-अपने तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि 5 साल जो कांग्रेस के रहे वह छत्तीसगढ़ के अन्य के साथ अन्याय और धोखा होते रहे, उन्होंने हर जगह या तो भर्तियां रोकी हैं। जहां थोड़ी-थोड़ी भर्ती हुई, वहां पर भारी भ्रष्टाचार किया गया।

ईवे बिल की अनिवार्यता सरकार का तानाशाही कदम



रायपुर। पूर्व मंत्री एवं विधायक उमेश पटेल ने ईवे बिल की छूट को समाप्त करने को भाजपा सरकार को तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा कि 24 मई को नया संकुलर जारी हुआ है, जिसमें ई वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है और इससे इस्पेक्टर राज चालू हो जायेगा। संकुलर में स्पष्ट है कि कनसाईमेंट को जांच करने का अधिकार हो जायेगा और पहले बाईर पर चेंकिंग होती थी। अब कनसाईमेंट में चेंकिंग शुरू हो जायेगी तो इससे इस्पेक्टर राज वापस होगा और सभी व्यापारी इससे प्रभावित होंगे। दूसरी बात यह है कि जो छोटे व्यापारी हैं जो गल्ला दुकान वाले, जो साड़ी का दुकान चलाते हैं, गांव में कोई जूते का दुकान चलाता है उनके लिये बड़ी समस्या होगी। उनको हर बार ईवे बिल जनरेट करने की अनिवार्यता है। अगर ई वे बिल जनरेट नहीं करते हैं तो पेनाल्टी भी बहुत ज्यादा होता है। जो ये संकुलर है लंबे समय में छत्तीसगढ़ व्यापार को बहुत नुकसान करेगा। जिस तरह से लोगो का रिवेन्यू बढ़ रहा है और सरकार से मांग करता हूँ कि संकुलर को जल्द से जल्द वापस ले। यह आदेश छत्तीसगढ़ के लिये बहुत नुकसान दायक है। पूर्व मंत्री एवं विधायक उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2018 में इस संकुलर को लायी गयी थी।

जीएसटी से छोटे/मध्यम व्यापारी ताबाह, अफसरशाही बेलगाम



रायपुर। जीएसटी संबंधित अनियमितताओं, जटिल और अव्यवहारिक प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने व्यवहारिक जीएसटी लादकर छोटे और मध्यम व्यापारियों को ताबाह करने का षड्यंत्र रचा है। अपनी नाकामियों पर पर्देदारी करने के लिये कुतर्क कर रहे हैं, भाजपाई बताये कि जीएसटी कमिश्नर आईएसए नहीं होगा तो क्या किसी संघो को बैच्योर्गे? सरलीकरण और सुविधाजनक बनाने का झंझा देकर व्यापारियों को टाटा गया। 1 जुलाई 2017 से लागू होने के बाद से अब तक लगभग 3000 से ज्यादा संसोधन किए जा चुके हैं उसके बावजूद आज भी व्यवहारिक और प्रक्रियागत दिक्कतें व्यापारियों को हो रही है। गैर इरादतन, मामूली त्रुटि और मानवीय भूल पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधान और व्यावहारिक है आरसीएम का प्रावधान भी तर्कहीन है। व्यवसाय रिवर्स चार्ज के लिए खुद ही खुद को बिल जनरेट करें, फिर उसका इनपुट क्लेम करें, उसे पटाए और खुद ही क्रेडिट ले जबकि उसके विरुद्ध पर तो उस माल पर टैक्स की देयता उसी पर आनी है।

भाजपा सरकार के पास नक्सलवाद खत्म करने की नीति नहीं



रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि गृहमंत्री प्रेस वार्ता करके बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए विपक्ष से सुझाव मांगे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए जो सुझाव दिए उसके बाद गृहमंत्री उस पर अमल करने के बजाय कहते हैं कि उन्हें विपक्ष की सलाह की आवश्यकता नहीं है सरकार नक्सल खत्म करने में सक्षम है फिर सलाह क्यों मांगें? नक्सल मामले में भाजपा की सरकार सिर्फ राजनीतिक बयान बाजी कर रही है और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि गृहमंत्री विजय शर्मा हर दिन नया बयान देते हैं कभी कहते हैं कि नक्सलियों के साथ वो वीडियो कॉलिंग से चर्चा करेंगे? कभी वह कहते हैं कि नक्सली उन्हें सुझाव दें कि नक्सलवाद छोड़ने के लिए सरकार से क्या अपेक्षा रखेंगे? कभी कहते हैं गोली मारेंगे, कभी कहते हैं कि नक्सलवाद समस्या का हल एनकाउंटर नहीं है, गृहमंत्री खुद कर पा रहे हैं। राज्य सरकार को अपनी नक्सली नीति को स्पष्ट करना चाहिए।

मंत्रियों की गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग फिजूल की कवायद



रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मंत्रियों की गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग पर तंज करते हुए कहा कि साय के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग फिजूल की कवायद है। 5 महीने में ही साय सरकार की सुशासन की पोल खुल गई। भाजपा सरकार के मंत्रियों और नेताओं के आम जनता के साथ दुर्व्यवहार जग जाहिर हो गया है, गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग लेने यह कहीं भी जाए लोकिन भाजपा में मिले कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करने की प्रशिक्षण को छोड़ नहीं सकते हैं। भाजपा सरकार के मंत्रियों और नेताओं को तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की अपनी आदत को छोड़ना होगा और आम जनता के मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना होगा। उनकी बुनियादी जरूरत को पूरा करना होगा और झूठ बोलना छोड़ना होगा, तभी गुड गवर्नेंस की सोच पूरा होगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों में गरीब असहाय मजबूर जनता की सेवा करना नहीं है। चंद्र पूंजीपतियों के आगे पीछे पूरी इनकी सरकार चलती है। 15 साल के रमन भाजपा सरकार के दौरान भी प्रदेश की जनता प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी से हताश और परेशान रही है।

गोंदवारा के फोम फैक्ट्री में लगी आग, दो महिला की मौत

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर आगजनी का मामला सामने आया है। गोंदवारा में स्थित एक फोम फैक्ट्री में अचानक आग लगी और इस आगजनी में दो महिला कर्मचारी झुलस गईं जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी फिलहाल पता नहीं लग सका है। पुलिस के मुताबिक यह फैक्ट्री बीच बस्ती में है लेकिन रिहायशी मकान काफी दूर दूर हैं। इस वजह से कोई जन हानि अधिक नहीं हुई। आग लगने की सूचना पर दमकल के कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मौके पर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, एस डी एम, एएसपी सिटी समेत अन्य अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। आग लगते वक फैक्ट्री में सात मजदूर काम कर रहे थे। इनमें पांच पुरुष, दो महिलाएं थीं। आग लगते ही पुरुष भाग निकले लेकिन महिलाएं दूसरे गेट से निकले के प्रयास में आग से फिर कर झुलस गईं। जिन्हें निकालकर अस्पताल भेजा गया लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इनके नाम नहीं मिल पाए हैं। इस फैक्ट्री में पलंग के गद्दे बनाने के लिए फोम का बड़ा भंडारण किया गया था और अन्य उपयोगी कैमिकल भी रखे थे। इनकी वजह से भी आग तेजी बढ़ रही है। उस पर तेज हवा से भी आग बुझाने में दिक्कत हो रही है।

प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़/राजधानी

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक सम्पन्न

ईएमआईएस पोर्टल पर मशीनों की टैगिंग सहित अन्य विषयों पर की गई चर्चा

रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन के कार्यों, समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा आज स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर में बैठक आहूत की गई।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशों का पालन करते हुए अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शासन की प्राथमिकता एवं समय सीमा के अंकित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने कहा गया। इसके

साथ ही बैठक में विभिन्न एजेंडों जैसे नियद नेह्लानन योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जननी निगरानी, टीकाकरण की अद्यतन स्थिति, सिकलसेल टैरिंग्स सहित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

सुरक्षा योजना, सिकलसेल, टीबी, एनीमिया स्क्रीनिंग, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र, आयुधान भारत योजना, 102 एंजुलेंस, 104 एंजुलेंस, 108 एंजुलेंस की सतत

कोपागुड़ा एवं जगदलपुर के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर घुमंतू मानसिक रोगियों के रेस्क्यू के लिए दिशा-निर्देश बैठक में दिए गए। इसके अलावा ईएमआईएस

पोर्टल पर मशीनों की टैगिंग के संबंध में कार्यशाला आयोजित करने, राज्य और जिला स्तरीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन, प्रस्तावित नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति प्रदाय करने सहित विभिन्न जिला अस्पतालों में स्टॉफ नर्स के पदों की संख्या बढ़ाने के संबंध में भी समीक्षा हुई। बैठक में विशेष सचिव श्री चंदन कुमार, प्रबन्ध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. जगदीश सोनकर, क्वारिंटर कम संचालक ऋतुप्रिया रघुवंशी एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन श्रीमती पद्मिनी

भोई उपस्थित थे। बैठक में मितानिन प्रोत्साहन राशि के राज्यों राशि भुगतान के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं कोटा विकासखण्ड के ग्राम पूर्वती में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा आयुधान भारत जन आरोग्य योजना, डॉ.खूबचंद

बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनागत क्लेम ऑडिट एमव्हीएसएसवाय मॉनिटरिंग, अनसेसिफाईड प्रकरण की भी समीक्षा की गई।

गुणवत्ता युक्त शिक्षा वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न

रायपुर। राज्य नीति आयोग द्वारा अमृत काल विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा विषय पर गठित वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की विशेष मौजूदगी में आज यहां नीति भवन नवा रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में वर्किंग ग्रुप के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नीति आयोग के सदस्य डॉ. के.सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूहों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए

निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र



विकास विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन ने विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में भी विभागीय जानकारी के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रखा। आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शारदा वर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्किंग ग्रुप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौड़िया, संयुक्त संचालक श्रीमती वत्सला मिश्रा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।